खबर पेज 7 पर

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

खबर पेज 8 पर

वर्ष -12 | अंक–25 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, सोमवार 16 – 31 मार्च 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

सुविचार

- अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है, जो जिंदगी भर आपके काम आती है।
- जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कुछ न कुछ रास्ता होता है..।
- जब आप एक ही जोक पर दुबारा नहीं हँसते तो एक ही दुःख पर दुबारा परेशान नहीं होना चाहिए।

शेरो-शायरी

- कौन कहता है वक्त तेज गुजरता है कभी किसी का इंतज़ार करके देखो।
- 'प्यार इंसान' से करो उसकी 'आदत' से नहीं... 'रुठों' उनकी बातों से मगर उनसे नहीं.... 'भूलो' उनकी गलतियाँ पर उन्हें नहीं.... क्यों की 'रिश्तों' से बढकर कुछ भी नहीं।

आईएमएफ की चेतावनी-ईरान जंग से दुनिया में बढ़ जाएगी महंगाई

धीमी हो जाएगी विकास की रफ्तार

निज संवाददाता : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को अब लगभग एक महीना हो गया है। इस दौरान, कई देशों में महंगाई तेजी से बढ़ी है। ज्यादातर देशों में गैस और तेल की सप्लाई को लेकर भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस संघर्ष की वजह से, छोटे देशों की तो बात ही छोड़िए, बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी हिल गई हैं। इन सबके बीच, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने अब एक बड़ी चेतावनी जारी की है। आईएमएफ ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। आने वाले समय में यह असर और भी गहरा हो सकता है। यह संघर्ष उन कई अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, जो अभी-अभी पिछले संकटों से उबरना शुरू ही हुई थीं। आईएमएफ के अर्थशास्त्रियों टोबियास एड्रियन और जिहाद अजौर द्वारा जारी एक विस्तृत विश्लेषण में कहा है कि यह संघर्ष पहले ही वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। ऊर्जा, खाद्य और वित्तीय बाजारों के माध्यम से इसका असर तेजी से फैल रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर देखा जा रहा है। खास तौर पर, होर्मूज स्ट्रेट को लेकर बनी अनिश्चितता ने वैश्विक सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि होर्मूज दुनिया की लगभग 25 से 30 फीसदी तेल सप्लाई और लगभग 20 फीसदी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के लिए एक अहम रास्ता है। इसके बंद होने के खतरे से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, और ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। आईएमएफ का कहना है कि इस संकट का असर सभी देशों पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। विकासशील और गरीब देश, जो ऊर्जा आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ने की आशंका है। खास तौर पर, एशिया और अफ्रीका के जिन देशों के पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं, उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में रुकावटों की वजह से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत, तेल और गैस का निर्यात करने वाले देशों को इस स्थिति से कुछ हद तक फायदा हो सकता है। ऊर्जा संकट के दुष्परिणाम अब खाद्य क्षेत्र में भी दिखाई देने लगे हैं; ईंधन की बढ़ती कीमतों और खाड़ी देशों से उर्वरकों की सप्लाई में रुकावटों की वजह से कृषि उत्पादन की लागत बढ़ रही है। **(शेष पृष्ठ 7 पर)**

बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन

निज संवाददाता : निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए हैं। कहा जा रहा है कि यह निर्वाचन आयोग का एक दिन में किए गए ट्रांसफर में से सबसे बड़ा फेरबदल है। आयोग ने बंगाल के 173 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, इनमें कोलकाता के 31 पुलिस स्टेशनों के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा 83 ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) का तबादला किया गया है। बीडीओ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर भी काम करते हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम पुलिस स्टेशनों के ओसी (प्रभारी अधिकारी) भी बदल दिए गए हैं। यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही उन सुनवाईयों के बीच उठाया गया है। जिनमें एक जनहित याचिका (पीआईएल) के ज़रिए 60 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पहले किए गए बड़े पैमाने पर तबादलों को चुनौती दी गई है। जिनमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी शामिल हैं। कोलकाता के भवानीपुर और पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों का भी तबादला किया गया। कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों के आईसी और ओसी के रूप में कार्यरत निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का भी तबादला किया गया है। कोलकाता में, एसटीएफ इंस्पेक्टर सौमित्र बसु भवानीपुर के नए ओसी होंगे। पार्क स्ट्रीट के नए ओसी निरुपम नाथ होंगे, और जोड़ासांको के ओसी सुशांत मंडल होंगे। नाथ और मंडल, दोनों को ही डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से लाया गया है। अलीपुर, गार्डनरीच, एंटाली, गरियाहाट, बहुबाजार और न्यू मार्केट पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों को भी बदला गया है। भांगड़ और पोलरहाट पुलिस स्टेशनों का कार्यभार संभालने के लिए दो नए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस में, 142 अधिकारियों का तबादला करके उन्हें आईसी या ओसी के तौर पर नई पोस्टिंग दी गई। इनमें से नौ तबादले पूर्वी मिदनापुर में किए गए, और इंस्पेक्टर शुभोब्रत नाथ को नंदीग्राम पुलिस स्टेशन का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया। जलपाईगुड़ी ज़िले में चार, कूचबिहार ज़िले में तीन, नदिया ज़िले में पांच, मुर्शिदाबाद और हुगली ज़िलों में चार-चार, पश्चिम मिदनापुर में दो, बीरभूम में छह, बांकुड़ा में चार, पुरुलिया में तीन, और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, हावड़ा और पश्चिम बर्दवान ज़िलों में एक-एक बीडीओ/एआरओ का तबादला किया गया है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने बंगाल के 15 ज़िलों में 83 बीडीओ का तबादला किया था। सीईओ मनोज अग्रवाल ने 84 बीडीओ के तबादले का प्रस्ताव दिया था। ईसी ने 83 तबादलों को मंज़ूरी दे दी, और केवल सिउड़ी- के बीडीओ के प्रस्तावित तबादले को खारिज कर दिया। पूर्वी मिदनापुर में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिले, जहां 13 तबादले हुए। इसमें नंदीग्राम के दोनों ब्लॉक शामिल हैं। दक्षिण 24 परगना में 11 और उत्तर 24 परगना में आठ तबादले हुए। नंदीग्राम- में चुनाव आयोग ने संजय सिकदर को नियुक्त किया है। नंदीग्राम- का कार्यभार देबोत्तम सरकार को सौंपा गया है। ये तबादले हाईकोर्ट में तबादला मामलों की सुनवाई सोमवार को फिर से शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले किए गए हैं।

15 मार्च के बाद ताबड़तोड़ ट्रांसफर

पिछले महीने 15 मार्च को पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले चुनावों की घोषणा के बाद से, चुनाव आयोग समय-समय पर अलग-अलग स्तरों के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी करता रहा है। तबादले की यह प्रक्रिया सबसे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारियों से शुरू हुई थी। मुख्य सचिव और गृह सचिव,बंगाल के डीजीपी, एडीजी के तबादले किए गए थे। दूसरे चरण में, बीच के स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए; जैसे प्रशासनिक अधिकारियों में ज़िलाधिकारी (डीएम), और पुलिस प्रशासन में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी कमिश्नर। अब प्रशासनिक ढांचे के सबसे निचले स्तरों पर तबादलों का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित हैं। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, और दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा।

बदलेगा बंगाल, नंदीग्राम में फिर खिलेगा कमल : धर्मेंद्र प्रधान

निज संवाददाता : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और 'मन की बात' कार्यक्रम के अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष आयोजन में सहभागी भी बने। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नंदीग्राम में इस बार भी कमल खिलना तय है। अब समय आ गया है बंगाल बदलेगा और विकास के नए युग की शुरुआत करेगा। बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित किया था। इस बार फिर से नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही वह भवानीपुर से भी पार्टी के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा, आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सदन में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र नंदीग्राम में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथियों के साथ संवाद का अवसर मिला। उन्होंने लिखा- नंदीग्राम केवल एक क्षेत्र नहीं, यह परिवर्तन की चेतना का प्रतीक है। यहां की जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में दृढ़ता से खड़ा है। कार्यकर्ताओं का जोश, अनुशासन और समर्पण स्पष्ट संकेत दे रहा हैइस बार भी नंदीग्राम में कमल खिलना तय है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, आज नंदीग्राम में 'मन की बात' कार्यक्रम के अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष आयोजन में सहभागी बनने का अवसर मिला। इस दौरान अन्न प्रसाद वितरण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।उन्होंने लिखा- लगभग 20 वर्षों से नंदीग्राम से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है। नंदीग्राम की यह भूमि बंगाली अस्मिता और परिवर्तन की चेतना का सशक्त प्रतीक रही है। यहां से उठी आवाज़ ने समय-समय पर पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब अन्याय, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊब चुका है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से मुक्ति का संकल्प अब जन-जन का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल की जनता एक स्वर में कह रही है- पालटनो दोरकार, चाइ बीजेपी सरकार (बदलने की जरूरत है, बीजेपी सरकार चाहिए) धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह बदलाव की लहर है, यह जन-आक्रोश है, यह एक नए और विकसित बंगाल के निर्माण का उद्घोष है। अब समय आ गया हैबंगाल बदलेगा और विकास के नए युग की शुरुआत करेगा।

बीजेपी के 'संकल्पपत्र' में रोजगार, शिक्षा व उद्योग समेत सात प्रमुख मुद्दों को मिलेगी प्राथमिकता

निज संवाददाता : बीजेपी अप्रैल के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी संकल्पपत्र (मैनिफेस्टो) जारी करने जा रही है। संकल्पपत्र में विस्तार में बताया जाएगा कि अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वह राज्य और राज्य के लोगों के लिए क्या करना चाहती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, मैनिफेस्टो में सात मुख्य मुद्दों को प्राथमिकता वाले एरिया के तौर पर रेखांकित किया जा रहा है। राज्य की खराब वित्तीय हालत को सुधारने से लेकर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर ग्रामीण विकास तक, कई घोषणाएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग पर भी कई आकर्षक वादे हैं। बीजेपी आखिरकार सिंगूर के बारे में कोई साफ घोषणा करने का रास्ता अपना सकती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, तो उन्होंने इंडस्ट्री वापस लाने पर कोई कमेंट करने से परहेज किया था। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि मैनिफेस्टो में इसका भी जिक्र होगा। गौरतलब है कि मैनिफेस्टो पब्लिश करने से पहले, बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के राज के खिलाफ एक 'चार्जशीट' पब्लिश की है। पिछले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आए और औपचारिक तौर पर चार्जशीट पेश की।

बीजेपी के 'प्रस्तावित' मैनिफेस्टो की मुख्य बातें

1. दिवालिया खजाने और गलत प्रशासनिक परंपरा से छुटकारा

- पिछले 15 सालों में तृणमूल के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाएगा। माफिया राज तुरंत खत्म किया जाएगा। कोयला, रेत, पत्थर जैसे अलग-अलग प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग जैसी लूट तुरंत रोकी जाएगी।
- पश्चिम बंगाल में बिज़नेस और कॉमर्स को मुश्किल बनाने वाले सभी माफिया सिंडिकेट के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' पॉलिसी अपनाई जाएगी।
- तृणमूल सरकार की गलत रिज़र्वेशन पॉलिसी को बदला जाएगा। जिन सभी कम्युनिटी को गलत तरीके से रिज़र्वेशन से बाहर रखा गया है, उन्हें रिज़र्वेशन के तहत लाया जाएगा।
- 'लक्ष्मी भंडार' स्कीम के तहत हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
- बेरोजगार युवाओं को 'युवासाथी' स्कीम के तहत हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
- सत्ता में आने के 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया चुका दिया जाएगा।
- राज्य सरकार में सभी खाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से भरी जाएंगी।
- सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर बेरोजगारों की निर्भरता कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे और पॉलिसी बनाई जाएंगी, जिससे नए ऑर्गनाइजेशन और मौके बनेंगे।
- हर साल राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कुल चार 'अग्निवीर' रिक्रूटमेंट कैंप लगाए जाएंगे।
- बीजेपी की लीडरशिप वाली राज्य सरकार आर्मी में बंगाल रेजिमेंट बनाने में एक्टिव रहेगी।
- राज्य के वेटलैंड्स और जंगलों को 'रामसर कन्वेंशन' के हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाएगा।
- महिलाओं की सेफ्टी पक्का करने के लिए हर तरह के कदम उठाए जाएंगे। पुलिस की सेंसिटिविटी बढ़ाई जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक्टिव किए जाएंगे और अपराधियों को कड़ी सज़ा दी जाएगी।
- सिक्योरिटी को पक्का करके गैर-कानूनी घुसपैठ रोकी जाएगी। इस देश में आने वाले विदेशियों के ठिकानों को पूरी तरह से काट दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके पश्चिम बंगाल को जिहाद-फ्री बनाया जाएगा।
- पहाड़ियों में स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने का पहले किया गया वादा भी निभाया जाएगा।
- कुरमाली और राजबंशी भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान दी जाएगी।

2. डेवलपमेंट प्राथमिकता है

- केंद्र सरकार के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में एक डीप सी पोर्ट बनाया जाएगा।
- दामोदर, रैडक, भागीरथी और गंगा जैसी नदियों पर पुल बनाकर इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया जाएगा।
- सुंदरबन से दार्जिलिंग पहाड़ियों तक पूरे राज्य को नेशनल हाईवे से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यह दूरी सात से आठ घंटे में तय करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।
- नॉर्थ बंगाल में खेती, इंडस्ट्री और टूरिज्म का डेवलपमेंट।
- मालदा और बालुरघाट एयरपोर्ट से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट शुरू करने का इंतज़ाम किया जाएगा।

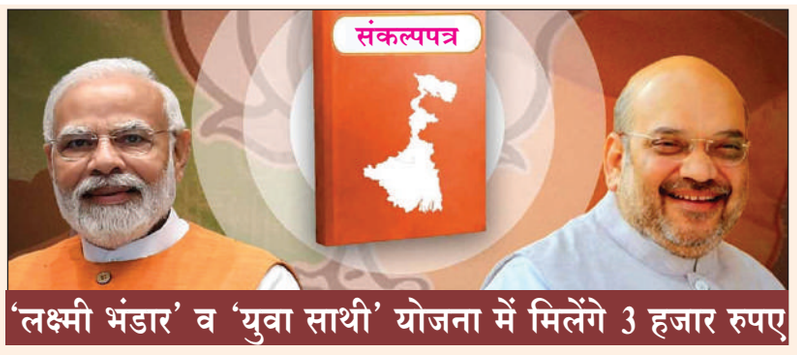

'लक्ष्मी भंडार' व 'युवा साथी' योजना में मिलेंगे 3 हजार रुपए

- ज़मीन की रुकावटें हटाकर रेलवे प्रोजेक्ट्स को तेज़ किया जाएगा।
- विधान चंद्र रॉय की विरासत का सम्मान करते हुए राज्य में चार नए शहर (जैसे दुर्गापुर, विधाननगर, कल्याणी) बनाए जाएंगे।
- शहरी इलाकों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा।

3. राज्य में काम का इंतज़ाम

- बीजेपी सरकार यह पक्का करेगी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी के बावजूद कमाई या रोज़ी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर न हो। पश्चिम बंगाल को एक मज़बूत इकॉनमी बनाना ही इस लक्ष्य को पाने का एकमात्र तरीका है।

4. ग्रामीण आर्थिक विकास

- केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य में लंबे समय तक बाढ़ कंट्रोल के उपाय।
- बॉर्डर वाले इलाकों में कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों को फायदा हो।
- किसानों के लिए बीज, खाद और पेस्टिसाइड की भरोसेमंद सप्लाई पक्की की जाएगी। पर्यावरण से जुड़े मामलों का भी ध्यान रखा जाएगा।
- यह पक्का किया जाएगा कि धान उगाने वाले किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। फसलों की खरीद-बिक्री में बिचौलियों को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- आलू उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे।) आईसीएआर के आलू रिसर्च सेंटर की मदद से पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही एक संगठन बनाया जाएगा, जो राज्य के आलू उगाने वाले किसानों के लिए मददगार होगा।
- पशुपालन और रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट जॉइंट वेंचर को बढ़ावा दिया जाएगा।)
- राज्य में कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे।) मछली पालन और मछुआरों के हितों की रक्षा करने और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।

5. इंडस्ट्री का भविष्य पक्का करना

- सिंगूर में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए स्थानीय ज़मीन मालिकों की इजाज़त से 1,000 एकड़ ज़मीन लेना।
- राज्य में डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चार बड़े इंडस्ट्रियल पार्क।
- माइनिंग समेत कोई भी इंडस्ट्री लगाने में एनवायरनमेंटल नियमों का सख्ती से पालन पक्का किया जाएगा।
- राज्य की बीजेपी सरकार दुर्गापुर और बर्नपुर में स्टील फैक्ट्रियां बनाने में एक्टिव रहेगी।
- आसनसोल, दुर्गापुर, बैरकपुर, हावड़ा और तारातला के इंडस्ट्रियल तालुका को फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी।
- चाय और जूट इंडस्ट्री को फिर से शुरू किया जाएगा।
- डिफेंस से जुड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। इच्छापुर गन एंड शेल फैक्ट्री और गार्डनरीच शिपबिल्डर्स को नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की जाएगी।
- पश्चिम बंगाल में एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फिर से शुरू किया जाएगा।
- महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए सरकारी बसों में फ्री सफर का इंतज़ाम किया जाएगा।
- कोलकाता-हावड़ा, बर्दवान, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर और सिलीगुड़ी में 'लॉजिस्टिक्स हब' बनाए जाएंगे।
- बीड़ी वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के ज़रिए बीड़ी वर्कर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा।
- बीजेपी सरकार बांग्ला सिनेमा की खोई हुई शान को वापस लाने की कोशिश करेगी। फिल्म इंडस्ट्री पर माफिया का कंट्रोल खत्म करके, फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और क्रू को क्रिएटिविटी का माहौल दिया जाएगा।
- पश्चिम बंगाल की कल्चरल दुनिया को पॉलिटिक्स से फ्री किया जाएगा।

6. शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन

- पश्चिम बंगाल में एजुकेशन का ट्रेडिशन फिर से शुरू किया जाएगा। सरकारी शैक्षिक संस्थान को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। टीचर्स की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब क्लासरूम्स को बदला जाएगा।
- लेफ्ट के बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण और ग्रासरूट लेवल की करप्ट एक्टिविटीज़ की वजह से पश्चिम बंगाल में हायर एजुकेशन को हुए नुकसान को ठीक करने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी।
- पश्चिम बंगाल में 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020' लागू की जाएगी।) शैक्षिक संस्थान में सभी खाली जगहें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से भरी जाएंगी।
- नॉर्थ बंगाल में आईआईटी और आईआईएम बनाने की पहल।
- राज्य में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की पहल।
- मेडिकल एजुकेशन के मौके बढ़ाए जाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में बदला जाएगा।
- बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासनिक इंतज़ाम किए जाएंगे।

7. हेल्थ सर्विस का डेवलपमेंट

- यह पक्का किया जाएगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काफी डॉक्टर और नर्स हों। साफ-सुथरा माहौल पक्का किया जाएगा।
- हेल्थ सर्विस सेंटर में 24 घंटे सर्विस पक्की की जाएगी।
- एक हेल्थ पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें बचाव के तरीकों पर ज़ोर दिया जाएगा।
- जैसे ही बीजेपी राज्य में सत्ता में आएगी, आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की जाएगी, जिससे पश्चिम बंगाल के लोगों को भारत के किसी भी हिस्से के किसी भी हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलेगा।
- दिव्यांग लोगों को स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे।

फिर होगा ममता व शुभेंदु के बीच महामुकाबला

नंदीग्राम और भवानीपुर में दोनों होंगे आमने-सामने

निज संवाददाता : वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में मुकाबला हुआ था। हालांकि नंदीग्राम चुनाव में ममता बनर्जी पराजित हुई थीं और भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थीं, लेकिन इस चुनाव में फिर से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने-सामने होंगे। भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच महामुकाबला होगा। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को फिर से भवानीपुर सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, जबकि शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर से उतारा है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुभेंदु अधिकारी उनमें से एक थे। जब चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, तब ममता बनर्जी ने अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा था। सीपीएम ने युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी को उतारा था। हालांकि, ममता और शुभेंदु के बीच की लड़ाई में सबकी दिलचस्पी थी। आखिर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उस लड़ाई में ममता को 1956 वोटों से हरा दिया। उन्हें 1 लाख 10 हजार 764 वोट मिले थे और ममता को 1 लाख 8 हजार 808 वोट मिले। इन दोनों दिग्गजों के बीच की लड़ाई में मीनाक्षी को 6 हजार 267 वोट मिले थे। हालांकि, वोट के रिजल्ट पर विवाद हुआ है। ममता ने कोर्ट में केस भी किया। लेकिन पिछले 5 सालों में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में तृणमूल सुप्रीमो को उनकी जीत के लिए कई बार चुनौती दी है। पांच साल बाद जगह बदल गई है, लेकिन, दोनों पार्टियों के दो बड़े नेता फिर से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखेंगे। पांच साल पहले ममता नंदीग्राम गई थीं और इस बार शुभेंदु भवानीपुर आए हैं। इस बार भवानीपुर में लड़ाई कैसी हो सकती है? राजनीतिक विश्लेषक इसका बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अपने-अपने हिसाब से हिसाब लगा रही हैं। बता दें कि ममता भवानीपुर को अपनी बड़ी बहन कहती हैं। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी भवानीपुर से उपचुनाव जीता था। उन्हें सीपीएम उम्मीदवार नंदिनी मुखर्जी से 54 हजार ज्यादा वोट मिले थे। इस चुनाव में उन्होंने लेफ्ट को हराया था और राज्य की मुख्यमंत्री बनी थीं। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता को भवानीपुर में 65 हजार 520 वोट मिले थे। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की दीपा दासमुंशी को 40,219 वोट मिले थे। उस समय बीजेपी उम्मीदवार चंद्रकुमार बोस को 26,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। ममता 25,000 से ज्यादा वोटों से जीती थीं। 2021 के चुनाव में इस सीट से ममता बनर्जी नहीं लड़ीं। इसलिए शोभनदेव चटर्जी ने तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 73,505 वोट मिले थे। पांच साल पहले, इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार रुद्रनील घोष थे। उन्हें 44,786 वोट मिले थे। शोभनदेव 28,500 से ज्यादा वोटों से जीते थे। बाद में, शोभनदेव ने भवानीपुर सीट खाली कर दी ताकि ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ सकें। भवानीपुर में उपचुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर, 2021 को घोषित किए गए थे। उपचुनाव में ममता को 85,263 वोट मिले थे। बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल को 26,428 वोट मिले थे। ममता 58,835 वोटों से जीतीं थीं।

ममता बनर्जी के लिए बहुत खास है भवानीपुर

निज संवाददाता : इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों में से भवानीपुर विशेष रूप से चर्चा में है। कारण, इस सीट से एक बार फिर मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। बड़ी बात यह कि उनके खिलाफ बीजेपी ने भवानीपुर सीट से राज्य के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होती है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ही निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व भवानीपुर जितना है। इस सीट का चुनावी सफर राज्य में कांग्रेस के प्रभुत्व से लेकर टीएमसी के उदय तक के परिवर्तन को दर्शाता है। ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाने वाला भवानीपुर हमेशा से टीएमसी का इतना मजबूत गढ़ नहीं था। तृणमूल सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में पार्टी बैठक में नेताओं से अलर्ट रहने को कहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 3 दिनों में 50 लोगों को हटाया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने कई पार्षदों की भूमिका पर भी नाराजगी जताई। अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के बारे में बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा- भवानीपुर में हर कोई मुझे जानता है। घर बदलने की बात होने के बावजूद मैंने भवानीपुर नहीं छोड़ा। मेरी मां ने मुझे यह घर बदलने नहीं दिया। गौरतलब है कि देश की आजादी के बाद दशकों तक दक्षिण कोलकाता की ये सीट कांग्रेस का गढ़ और राज्य के कुछ सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों का गृह क्षेत्र रही। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में और बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस सीट से चुनाव लड़ा और जीता। मीरा दत्ता गुप्ता और रथिन तालुकदार जैसे अन्य कांग्रेसी दिग्गजों ने भी इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जिससे भवानीपुर की प्रतिष्ठा पार्टी के प्रमुख शहरी गढ़ों में से एक के रूप में मजबूत हुई। भवानीपुर कई सालों तक कांग्रेस के प्रभाव में मजबूती से बना रहा। वामपंथी केवल 1969 में थोड़े समय के लिए ही इस सीट पर कब्जा कर पाए। जब इस सीट का नाम बदलकर कालीघाट निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया। सीपीआई (एम) नेता साधन गुप्ता 1953 में इसी सीट से भारत के पहले दृष्टिबाधित सांसद बने। भवानीपुर की राजनीतिक यात्रा ने 1972 में एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, जब परिसीमन के बाद यह निर्वाचन क्षेत्र चुनावी मानचित्र से गायब हो गया। लगभग 4 दशकों तक यह सीट केवल राजनीतिक स्मृति में ही मौजूद रही। 2011 के परिसीमन में इसे फिर से जीवित किया गया।

हिंसामुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए ओसी को दिए गए अहम निर्देश

निज संवाददाता : राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलकाता पुलिस की तरफ से शहर के थानों के इंचार्ज अधिकारियों (ओसी) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में 2021 और 2024 में चुनाव से जुड़ी गड़बड़ी के लिए ज़िम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द पहचान करके उन पर मुकदमा चलाएं। शहर भर के पुलिस थानों के ओसी के साथ बैठक में, सीनियर आईपीएस अधिकारियों ने कहा कि पुलिस उन इलाकों और मोहल्लों की मैपिंग करेगी जहां चुनाव में हिंसा का इतिहास रहा है और यह पक्का करेगी कि वोटरों पर कोई दबाव, धमकी या डर न हो। वर्चुअल मीटिंग के दौरान, लालबाजार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि पहचाने गए गड़बड़ी करने वालों पर मुकदमा कोलकाता में मतदान के दिन (23 अप्रैल) से कम से कम सात दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए। पुलिस थानों के एंटी-क्राइम अधिकारियों जो बार-बार अपराध करने वालों को ट्रैक करते हैं को सभी गैर-ज़मानती अरेस्ट वारंट का तामील पक्का करने के लिए कहा गया है। अगर कई रेड के बाद भी कोई आरोपी पकड़ में नहीं आता है, तो पुलिस उस व्यक्ति को ''घोषित अपराधी'' घोषित करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मांगेगी। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा-अधिकारियों को सेंट्रल फोर्स के साथ मिलकर सभी विधानसभा सीटों पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उपाय करने को कहा गया। एरिया डॉमिनेंस एक्सरसाइज (क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास) पोलिंग से दो दिन पहले पूरी होनी चाहिए। लालबाजार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद ओसी की जिम्मेदारियों को काफी पहले से तय करना था। चुनाव आयोग ने पुलिस को कोलकाता में पोलिंग से पहले तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया था। चर्चा में चुनाव से पहले और बाद की घटनाओं के रिकॉर्ड के आधार पर हिंसा के लिए कमजोर इलाकों की पहचान करने पर फोकस किया गया। ऑफिसर ने कहा-ऑफिसर्स अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों और बस्तियों का दौरा करेंगे, वोटर्स से बातचीत करेंगे, किसी भी तरह की धमकी का आकलन करेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

थानों के ओसी को जारी कुछ निर्देश :

सेक्टर ऑफिसर्स (10-12 पोलिंग स्टेशनों की देखरेख करने वाले सरकारी ऑफिसर्स) ओसी के साथ सलाह करके हर विधानसभा सीट में खतरों और धमकी के लिए कमजोर घरों की लिस्ट तैयार करेंगे। हर सीट के सेक्टर ऑफिसर्स की लिस्ट सभी ओसी के साथ शेयर की जाएगी। शक वाले उपद्रवियों को पोलिंग से पहले हटा देना चाहिए और उन पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। अधिकारियों को मिली-जुली आबादी वाले इलाकों और हिंसा की हिस्ट्री वाले पोलिंग स्टेशनों पर जाना चाहिए, और पुलिस के डिविजनल डिप्टी कमिश्नरों के ज़रिए लालबाजार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। चुनावी ईमानदारी बनाए रखने के चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, राज्य के मुख्य सचिव ने हाल ही में सभी डिपार्टमेंट को फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव पक्का करने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं।

भारत सेवाश्रम संघ ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले साधु को संस्था से निकाला

उत्पल महाराज को बीजेपी ने कालियागंज से बनाया है उम्मीदवार

निज संवाददाता : भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले एक साधु को संघ से निकाल दिया है। एक आंतरिक नोट में, बीएसएस ने इस कदम को संघ के नियमों के सिद्धांतों से गंभीर रूप से अलग और एक ''राजनीतिक'' कदम बताया। इसके शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय की बैठक के बाद जारी आंतरिक परिपत्र के अनुसार, संघ ने स्वामी ज्योतिर्मयानंद, जिन्हें उत्पल महाराज के नाम से भी जाना जाता है, को निकाल दिया है। उनको बीजेपी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज चुनाव क्षेत्र से खड़ा किया है। परिपत्र में कहा गया कि चुनाव लड़ने का फैसला करके, साधु संन्यास और अनुशासन के रास्ते से भटक गए हैं, जिसकी उम्मीद मठ के सदस्यों से की जाती है। इसमें कहा गया कि पार्टी राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेना संघ के आदर्शों के खिलाफ है। संघ के रुख को दोहराते हुए, संगठन ने कहा कि वह राजनीतिक मामलों में पूरी तरह से तटस्थता रखता है और अपने साधुओं, ब्रह्मचारियों और साथियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने या उसका समर्थन करने से रोकता है। नोट में आगे चेतावनी दी गई कि राजनीतिक जुड़ाव या दुनियावी कामों की तरफ कोई भी झुकाव संघ के मूल्यों के लिए ज़रूरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को कमज़ोर करता है, और इशारा किया गया कि दूसरों द्वारा इसी तरह के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्पल महाराज ने बताया कि उन्होंने बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए राज़ी होने से पहले ही बीएसएस हेडक्वार्टर को अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, और बीएसएस ने बस उनके इस्तीफ़े को ''कन्फर्म'' किया है। उन्होंने कहा-मुझे बीएसएस के नियमों की साफ़ समझ है कि संघ से जुड़ा कोई साधु सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता, और उनके (बीएसएस) पत्र जारी करने से पहले ही, मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने कहा-बस इतना ही है कि संघ के अधिकारियों ने आदेश से अलग होने के मेरे फैसले को माना और कन्फर्म किया। गौरतलब है कि कोलकाता में स्थित भारत सेवाश्रम संघ ने एक सामाजिक-धार्मिक और समाज-सेवी संस्था के तौर पर शुरू किया था, और इस बात पर ज़ोर दिया कि दुनियावी मामलों से अलग रहना उसकी सोच का आधार है।

चुनाव आयोग ने मतदान कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया

निज संवाददाता : राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रीसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, काउंटिंग स्टाफ, माइक्रो ऑब्जर्वर और वोटिंग से जुड़े दूसरे अधिकारियों का भत्ता बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। यह बदलाव काफी समय बाद किया गया। गाइडलाइंस के मुताबिक, पिछला बड़ा बदलाव 2014-2016 के बीच हुआ था। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्रीसाइडिंग ऑफिसर और काउंटिंग सुपरवाइजर को पहले रोजाना 350 रुपए मिलते थे। यह बढ़कर 500 रुपए हो गया है। पोलिंग ऑफिसर को पहले रोजाना 250 रुपए मिलते थे। अब उन्हें 400 रुपए मिलेंगे। काउंटिंग असिस्टेंट को रोजाना 250 रुपए मिलते हैं। यह बढ़कर 450 टका हो गया है। इसी तरह ग्रुप डी कर्मचारियों को पहले रोजाना 200 रुपए मिलते थे। यह बढ़कर 350 रुपए हो गया है। वीडियो सर्विलांस, अकाउंटिंग टीम, कॉल सेंटर, फ्लाइंग स्काड, मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज स्टाफ का अलाउंस बढ़ा दिया गया है। पहले उन्हें रोज़ाना 1000 से 1200 रुपए मिलता था। अब उन्हें 2000 से 3000 रुपए दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो ऑब्जर्वर का भत्ता रोज़ाना 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। सीएपीएफ और ऑफिसर्स का भत्ता : सीएपीएफ और ऑफिसर्स की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। 15 दिन से कम ड्यूटी पर रहने वाले गजेटेड ऑफिसर्स का अलाउंस 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। 15 दिन से ज़्यादा का वीकली रेंट 1250 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। 15 दिन से कम ड्यूटी पर रहने वाले कांस्टेबलों का भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। पोलिंग और काउंटिंग के इंचार्ज स्टाफ का खाने का भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, सेक्टर अधिकारियों और सहायक खर्च पर्यवेक्षकों का भत्ता 7500 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि पोलिंग कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने का फैसला उनके काम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में कोलकाता के अस्पताल का कीर्तिमान

♦ विदेश में गलत इलाज का शिकार हुए एक डच टूरिस्ट को दिया नया जीवन

निज संवाददाता : नीदरलैंड का एक टूरिस्ट विदेश में गलत डायग्नोसिस और उसके कारण बढ़ती शारीरिक दिक्कतों का शिकार हो गया था। लेकिन आखिरकार कोलकाता के अनुभवी डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दिया। उसके ब्रेन ट्यूमर को, जिसे लंबे समय से दूसरी बीमारी समझकर नज़रअंदाज़ किया जा रहा था, कामयाबी से निकाल दिया गया। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीदरलैंड का रहने वाला यह टूरिस्ट कई महीनों से तेज़ सिरदर्द, नज़र की दिक्कत और शारीरिक संतुलन की कमी से परेशान था। यूरोप में अलग-अलग जगहों पर इलाज करवाने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं मिला। वहां, डॉक्टरों ने शुरू में कहा कि यह एक आम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या स्ट्रेस से जुड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन दिन-ब-दिन बिगड़ती गई। टूरिज्म और काम के लिए कोलकाता आने के बाद, उस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और बिगड़ गई। उसे शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल सीएमआरआई सीके बिड़ला हास्पीटल ले जाया गया। वहां के न्यूरोसर्जन ने बिना कोई रिस्क लिए एमआरआई और सीटी स्कैन करने का फैसला किया। टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि आदमी के दिमाग के बहुत सेंसिटिव हिस्से में एक बड़ा ट्यूमर जम गया था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर ट्यूमर उसी जगह पर होता जहां वह था, तो टूरिस्ट अंधा हो सकता था या हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो सकता था। जल्दी से फैसला लेकर एक मुश्किल सर्जरी की योजना बनाई गई। कुछ घंटों की सांस रोककर की गई सर्जरी के बाद, डॉक्टर ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालने में कामयाब रहे। आधुनिक प्रौद्योगिकी और डॉक्टरों की काबिलियत की मदद से, सर्जरी बिना किसी बड़े साइड इफेक्ट के पूरी हो गई। सर्जरी के बाद, डच टूरिस्ट जल्दी ठीक हो गया। न सिर्फ उसकी आंखों की समस्या दूर हो गई, बल्कि वह अब नॉर्मल तरीके से चल भी पा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर दुनिया में कोलकाता के मेडिकल सिस्टम की क्वालिटी को सामने लाया। खासकर जब यूरोप जैसे विकसित देशों में भी इस बीमारी की पहचान करना मुमकिन नहीं था, तब कोलकाता के डॉक्टरों ने सही समय पर सही डायग्नोसिस करके एक मिसाल कायम की। इससे यह साबित होता है कि कोलकाता अब एडवांस्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (उन्नत चिकित्सा अवसंरचना) और काबिल डॉक्टरों के कॉम्बिनेशन के साथ एक वर्ल्ड-क्लास मेडिकल सेंटर के तौर पर उभर रहा है। बीमार टूरिस्ट और उसके परिवार ने कोलकाता के डॉक्टरों का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल सिस्टम पर उनका भरोसा बहुत बढ़ गया है। इस कामयाबी से मेडिकल टूरिज्म के फील्ड में कोलकाता की जगह और मजबूत होने की उम्मीद है।

घरों में बर्तन धोकर गुजारा करने वाली कलिता माझी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार

पीएम मोदी भी कर चुके हैं उनके सेवाभाव की सराहना

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने लगी है। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम हैं। कई वरिष्ठ और नामी नेताओं के भी नाम है, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। यह नाम कलिता माझी का है। कलिता माझी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं। उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यह दूसरी बार है, जब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। कलिता माझी नौकरानी का काम करके हर महीने 3000 से 4000 रुपये ही कमा पाती हैं। उन्हें बीजेपी ने पूर्व बर्दवान के आउसग्राम विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया है। कलिता माझी के पति का नाम सुब्रतो माझी है। सुब्रतो प्लंबर का काम करते हैं। कलिता माझी ने बताया कि वह कई वर्षों से बीजेपी की सदस्य हैं। वह समय निकालकर बीजेपी के लिए काम करती हैं। कलिता ने कहा कि जब बीजेपी ने उन्हें पहली बार टिकट दिया था तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा। उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। कलिता ने बताया कि वह बहुत गरीब हैं। वह जब पहली बार चुनाव लड़ीं तब भी खाली हाथ थीं और इस बार भी प्रचार के लिए लोगों के घर जाकर वोट मांगेंगी। कलिता ने कहा कि जब पिछली बार उन्हें हार मिली तो वह फिर से घरों में बर्तन धोने का काम करने लगीं। इस बार फिर उन्हें यकीन नहीं था कि बीजेपी टिकट देगी। लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर फिर भरोसा जताया है, वह पूरी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगीं। और जीतीं तो उसी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम करके दिखाएंगीं। कलिता माझी कहती हैं कि वह नौकरानी का काम करती है और इसलिए जमीनी स्तर से जुड़ी हैं। उन्हें आम आदमी के मुद्दों और गरीब परिवारों की दुर्दशा के बारे में बारीकियों से पता है। वह इस बार चुनाव जीत जाती हैं तो गरीबों के विकास के लिए काम करेंगी। कलिता ने कहा कि उनके लिए चुनाव का मुख्य मद्दा अपने गांव के लोगों के लिए काम करना है। उनकी हर तरह से मदद करना होगा। कलिता ने कहा कि उनका सपना है कि वह इलाके में गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाएं। अभी इलाके के लोगों को इलाज के लिए बर्दवान शहर जाना पड़ता हैं। इलाके में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार की कमी है। जीतने पर वह इन मुद्दों पर भी काम करेंगी। कलिता कहती हैं कि घर के कमजोर आर्थिक हालात की वजह से वह ज्यादा पढ़-लिख नहीं पाईं। ऐसे में अगर वह चुनाव जीतती हैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाई के अवसर देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। माझी बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं। वह बंगाल पंचायत चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पश्चिम बंगाल की आउसग्राम विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कलिता माझी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कलिता की सराहना करते हुए उन्हें राजनीति में एक उदाहरण और समाज के लिए उम्मीद बताया। पीएम मोदी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में आउसग्राम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कलिता माझी राजनीति में एक मिसाल की तरह हैं। स्वाभिमानपूर्वक गुजर-बसर करने वाली कलिता जी अपने सेवाभाव से समाज के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने 23 पदों से दिया इस्तीफा

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 पदों से इस्तीफा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि उनके इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री राज्य की तमाम बोर्ड की अध्यक्ष थीं। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय खुद से लिया है। इनमें राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्ष और इको-टूरिज्म सलाहकार बोर्ड जैसे कई बड़े पद भी शामिल हैं। ममता 2026 के विधानसभा चुनावों में अपने परंपरागत गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। यहां पर उन्हें घेरने के लिए बीजेपी ने नेता विपक्ष और ममता के पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। ममता इस सीट से चार बार जीत चुकी हैं। ममता के चुनावों के बीच एकदम से विभिन्न 23 पद छोड़ने को लेकर आधिकारिक पत्र जारी कर दिए

गए हैं। ममता ने जिन पदों को छोड़ा है। उनमें नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समिति के साथ वेस्ट बंगाल उर्दू अकादम का भी पद शामिल है।ममता ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में कहा है कि वह उनके सभी पदों से इस्तीफा स्वीकार करने के जरूरी कदम उठाए जाएं। चाहे वे पद सूची में शामिल हों या नहीं। ममता ने अचानक से तमाम पद क्यों छोड़े हैं। इसका कारण उन्होंने पत्र में नहीं बताया है। उन्होंने जिन पदों से इस्तीफा दिया है वे सभी पद एडमिनिस्ट्रेटिव और कमिटी के प्रमुख के पद हैं। ऐसी चर्चा है कि ममता ने ये सभी पद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लाभ के पद से जुड़े नियमों को लेकर संभावित कानूनी चुनौतियों से बचना है। भारतीय कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार कुछ ऐसे सरकारी पदों पर होता है जिन्हें लाभ का पद माना जाता है, तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। टीएमसी के नेताओं के अनुसार उन्होंने यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने, किसी भी ऐसे विवाद को रोकने के लिए उठाया है, जिसे विपक्ष उनके नामांकन दाखिल करने से पहले उठा सकता था।

स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नवान्न के सख्त दिशानिर्देश

निज संवाददाता : राज्य प्रशासन 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी सरकारी विभागों और अधिकारियों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, पारदर्शी और शांतिपूर्ण हों। राज्य सचिवालय नवान्न से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की अशांति या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चुनावों में पारदर्शिता पक्का करने के लिए मुख्य सचिव की तरफ से जारी गाइडलाइंस में 7 बातों पर ज़ोर दिया गया है। ये हैं :

1. हिंसा-मुक्त माहौल: चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा को सख्ती से रोका जाएगा।
2. डराना-धमकाना बंद करें: यह पक्का किया जाना चाहिए कि कोई भी वोटर किसी से डरा-धमका न सके।
3. लालच-मुक्त चुनाव : वोटरों को किसी भी तरह के गिफ्ट या पैसे से प्रभावित नहीं किया जा सकता।
4. नकली वोट रोकने के लिए सख्त कदम: नकली वोट या ठप्पा को रोकने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है।
5. बूथ पर कब्ज़ा रोकने के लिए: बूथ जाम करना या पोलिंग स्टेशन पर गैर-कानूनी तरीके से जमा होना पूरी तरह से मना है।
6. वोटरों के आने-जाने में कोई रुकावट नहीं: अगर सोर्स जैमिंग या वोटरों को घर से निकलने से रोकने की घटना हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7. सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी नज़र: नोटिफिकेशन में यह साफ़

अधिसूचना में की गई ज़ीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा

किया गया है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का किसी भी तरह से उल्लंघन न हो। सरकारी अधिकारियों से लेकर सभी लेवल के कर्मचारियों को इस मामले में खास तौर पर जागरूक रहने का निर्देश दिया गया है। नवान्न ने कहा कि यह गाइडलाइन हर सरकारी विभाग, सरकारी संगठन, ऑटोनॉमस संगठन और लोकल म्युनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल के हर कर्मचारी तक पहुंचाई जाए। यहां तक कि यह निर्देश ज़मीनी स्तर पर पहुंचा है या नहीं, इसके सबूत के तौर पर 25 मार्च शाम 5:30 बजे तक एक खास ईमेल आईडी (wbla-compliance@gmail.co) पर कन्फर्मेशन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। प्रशासन की इस पहल को देखकर राजनीतिक हलकों का मानना है कि पिछले चुनावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य पहले से ही अलर्ट है।

मौजूदा सरकार का मुख्य लक्ष्य यह पक्का करना है कि हर वोटर बिना किसी डर या दबाव के अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए यह मैसेज भी साफ़ किया गया है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्देशों का पालन नहीं करता है या मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

ममता के विकास पर भरोसा करके पूर्व माओवादी नेता ने छोड़ी बंदूक

निज संवाददाता : वह थोड़ी देर पहले सिर पर फूलों से भरी टोकरी लेकर घर लौटी हैं। छोटी बालकनी पर बुज़ुर्ग लक्ष्मी सरदार अपने थके शरीर को थोड़ा आराम दे रही थीं। दस फुट गुणा दस फुट का मिट्टी का घर। वहीं वह रहती हैं। वह सूखे माहुल फूल बेचती हैं, जिससे उन्हें प्रति किलोग्राम केवल 35 रुपए की कमाई होती है। उस थोड़ी सी कमाई के साथ, वह राज्य सरकार के भत्ते और खाद्य साथी प्रोजेक्ट से मिलने वाले राशन पर अपना परिवार चलाती हैं। पूर्व माओवादी नेता शोभा सिंह सरदार की मां इसी तरह अपना परिवार चलाती हैं। वह लंबे समय से भारी मन से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हैं। कई सालों बाद, उसकी बेटी जेल से रिहा होकर घर लौट आई है। अब मां और बेटी एक साथ नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही हैं। कई कमियों और शिकायतों के बावजूद, लक्ष्मी को मौजूदा राज्य सरकार पर भरोसा है। उनकी बेटी शोभा को भी यही भरोसा है। और इसीलिए वह इस बार (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव) चुनाव में हिस्सा लेना चाहती है। शोभा कभी राजनीतिक उथल-पुथल और कट्टर वामपंथ के असर में आकर क्रांतिकारी बन गई थी। लेकिन अब उसने वह पहचान छोड़ दी है और एक आम आदमी की तरह शांत, सामान्य ज़िंदगी जीना चाहती है। उसका सपना

इस बार लेंगी मतदान में हिस्सा

अब अपनी मां के साथ एक सुरक्षित परिवार बसाना है। झाड़ग्राम के बेलपहाड़ी थाने के भूलाबेड़ा इलाके के मजुगोरा गांव की एक आम लड़की। सिर्फ़ बारह-तेरह साल की उम्र में उसे ज़ुल्म के माहौल में अपना गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर वह माओवादी स्काड में शामिल हो गई और धीरे-धीरे एक ताकतवर माओवादी नेता बन गई। जल्द ही उसका नाम फैल गया-शोभा सिंह सरदार उर्फ चंदना सिंह। स्काड में करीब पांच साल रहने के बाद, 2010 में एक केस में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद, उसे पंद्रह साल लंबे सुधार गृह में बिताने पड़े। वह पिछले साल जुलाई में जमानत पर जेल से रिहा हुई और अपने गांव लौट आई। आज, 33 साल की शोभा की बातें अफसोस से भरी हैं। असल में, पिछले 15 सालों में जंगलमहल के गांव पूरी तरह बदल गए हैं। अब ज़िंदगी के कीमती पलों को खोने का दर्द उसे बहुत हिला देता है। पढ़ाई न कर पाना, बचपन और जवानी की सामान्य ज़िंदगी से दूर रहना सब कुछ बहुत बड़ा दर्द है। शोभा कहती है कि जब उसने गांव छोड़ा था, तो इलाके में सड़कें, पीने का पानी, स्कूल या हेल्थ सेंटर नहीं थे। गांव पूरी तरह से अलग-थलग थे। अब वह तस्वीर बदल गई है। बच्चे जूते पहनते हैं और साइकिल से स्कूल जाते हैं, और उन्हें पढ़ाई के लिए सरकारी मदद भी मिलती है। शोभा ने मौजूदा सरकार के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर भी खुशी जताई। खासकर महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी भंडार' प्रोजेक्ट का ज़िक्र करते हुए उसने कहा कि पहले गांव की महिलाओं के पास पैसे नहीं थे। अब उन्हें हर महीने कुछ पैसे मिल रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। इसके अलावा, वह युवा कम्युनिटी के लिए 'युबासाथी' प्रोजेक्ट को भी एक पॉजिटिव चीज़ के तौर पर देखती है। जंगलमहल में इस बदलाव ने शोभा को पॉजिटिव बना दिया है। हालांकि, अपनी ज़िंदगी के स्टेटस के लिए उसका अनुरोध है कि सरकार उसे रहने लायक घर दे और नौकरी का इंतज़ाम करे। उसके शब्दों में-मां बूढ़ी है, उसे इलाज की ज़रूरत है। उसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए नौकरी चाहिए। आँगन में फूल सुखाते हुए मां लक्ष्मी सरदार ने साफ़-साफ़ कहा-हमें दया आती है। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जंगल और जेल में लंबी ज़िंदगी बिताने के बाद, शोभा ने अपनी ज़िंदगी का बहुत समय गंवा दिया है। अब उसकी बस यही इच्छा है कि वह खुले आसमान के नीचे, एक आम इंसान की तरह शांति से रहे।

कोलकाता नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर बनीं स्मिता पांडे

निज संवाददाता : चुनाव आयोग द्वारा स्मिता पांडे को सिविक बॉडी (नागरिक निकाय) का एग्जीक्यूटिव हेड नियुक्त करने के बाद कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को पहली महिला कमिश्नर मिल गईं। यह कदम चुनाव आयोग के उस ऑर्डर का हिस्सा है जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (डीईओ) को हटाया गया था। केएमसी कमिश्नर उत्तर कोलकाता के डीईओ के तौर पर काम करते हैं। 2005 बैच की आईएएस ऑफिसर, पांडे 12 दिनों में दूसरी केएमसी कमिश्नर बनीं। उन्होंने 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर अंशुल गुप्ता की जगह ली, जिन्हें राज्य सरकार ने 6 मार्च को नियुक्त किया था। कोलकाता नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा-स्मिता पांडे केएमसी कमिश्नर बनने वाली पहली महिला होंगी। मालूम हो कि नगर निगम के लगभग सभी विभाग पुरुष ऑफिसर हेड करते हैं, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़कर, जिसे एक महिला लीड करती हैं। पांडे केएमसी के लिए नई नहीं हैं। उन्होंने जनवरी 2013 और फरवरी 2014 के बीच कोलकाता एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (केईआईआईपी) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर रैंक के तौर पर काम किया, जो शहर के ड्रेनेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड एक इनिशिएटिव है। नवंबर 2025 में, उन्हें एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा बीरभूम, पूर्व बर्दवान और पश्चिम बर्दवान के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर और उत्तर दिनाजपुर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम किया है, और इससे पहले कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है।

लखनऊ में जन्मी और पली-बढ़ी पांडे के पास लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्लांट साइंस में मास्टर डिग्री और एमबीए है। बाद में उन्होंने कलकत्ता

विश्वविद्यालय से एलएलएम की डिग्री हासिल की। आने वाले हफ्तों में पांडे को केएमसी कमिश्नर और उत्तर कोलकाता की डीईओ के तौर पर अपनी दोहरी भूमिकाओं में बहुत कुछ करना होगा। डीईओ के तौर पर, वे सात विधानसभा क्षेत्रों: चौरंगी, एंटाली, बेलेघाटा, जोड़ासांको, श्यामपुकुर, मानिकतला और काशीपुर-बेलगछिया में पोलिंग की देखरेख करेंगी।

चुनाव ड्यूटी उनके लिए नई नहीं है। उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनावों के दौरान दक्षिण कोलकाता की डीईओ के तौर पर काम किया था। वित्तीय वर्ष खत्म होने पर वे कमिश्नर का भी चार्ज संभालेंगी, जब नगर निगम के असेसमेंट डिपार्टमेंट पर डिफॉल्टर्स और बड़े टैक्सपेयर्स से पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का दबाव होता है। प्रॉपर्टी टैक्स केएमसी की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। 1951 से कमिश्नर केएमसी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच को हेड कर रहे हैं। उससे पहले, एग्जीक्यूटिव हेड को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के कलकत्ता कॉर्पोरेशन के पहले सीईओ थे।

महानगर में बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों की संख्या दो साल में तीन गुना बढ़ी

निज संवाददाता : महानगर कोलकाता में बिना हेलमेट और बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है। इन आंकड़ों के आने से राज्य प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। राज्य परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल ऐसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की संख्या पांच लाख को पार कर गई है। यह संख्या सिर्फ दो साल में लगभग तीन गुना बढ़ गई है, जिससे प्रशासन में चिंता बढ़ गई है।

परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जहां 2023 में बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के खिलाफ करीब 1.7 लाख मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गए। 2025 में यह संख्या 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। यानी, बहुत कम समय में कानून तोड़ने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। आंकड़े यह भी कहते हैं कि सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, बल्कि उपनगरों और आस-पास के जिलों में भी तस्वीर

आंकड़ों ने राज्य प्रशासन की चिंता बढ़ाई

यही है। बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना या बिना हेलमेट के पीछे बैठकर बाइक चलाना-दोनों ही मामलों में नियमों का उल्लंघन बढ़ रहा है। प्रशासन का मानना है कि यह ट्रेंड खासकर युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा है। पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रेगुलर छापेमारी के बावजूद हालात में ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि शहर के अलग-अलग ज़रूरी चौराहों पर हर दिन निगरानी बढ़ाई जा रही है, ई-चालान किए जा रहे हैं, फिर भी कई लोग नियमों का पालन करने में आनाकानी कर रहे हैं। कई मामलों में देखा जा रहा है कि जुर्माना भरने के बाद भी वही व्यक्ति दोबारा वही जुर्म कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, जागरूकता की कमी इस समस्या की मुख्य वजह है। सिर्फ़ कानून लागू करना काफ़ी नहीं है, बल्कि स्कूल और कॉलेज स्तर से लेकर हर स्तर पर सुरक्षित सफ़र के बारे में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। यह मैसेज कि हेलमेट पहनना सिर्फ़ कानून नहीं है, बल्कि जान बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है-और मज़बूती से पहुंचाना होगा। प्रशासन के एक हिस्से के मुताबिक, अगर सख़्त सज़ा के अलावा नियमित प्रचार, कैंपेन और टेक्नोलॉजी पर आधारित निगरानी बढ़ाई जाए तो इस ट्रेंड को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो, आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की आशंका है।

सतह पर नजर आ रही है टीएमसी की अंतर्कलह

निज संवाददाता : 10 साल पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जब बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था तब उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद विधान परिषद की गठन करूंगी। जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें दुखी और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, यह लोग विधान परिषद के जरिये सदन में जाएंगे। हालांकि 2021 में ममता सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था लेकिन संसद में स्वीकृति के लिए लंबित है। 2016 और 2021 में टीएमसी की टिकट से वंचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम थी इसलिए विरोध व विद्रोह विकराल रूप धारण नहीं किया था। जबकि 2026 में स्थिति भिन्न है, इस दफे 4 मंत्री सहित 74 विधायकों (33फीसदी) का टिकट कटा है। 15 विधायकों (7 फीसदी) का विधानसभा सीट बदला गया है। मौजूदा 135 विधायकों (60 फीसदी) को टिकट मिला है जबकि 141 नये चेहरे (47.95 फीसदी) को टिकट मिला है। लगभग आधे उम्मीदवार नए हैं, लिहाजा पुराने व कुछ नए जिन्हें नहीं मिला है, जमकर गदर काट रहे हैं। राज्य का शायद ही ऐसा कोई जिला नहीं बचा है, जहां से सड़कों पर खुलेआम विरोध प्रदर्शन की खबरें नहीं आ रही हों। जहां जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है, उसके समर्थक और विरोधी आपस में ही भिड़ने को तैयार दिख रहे हैं, कई जगहों पर तो दंगे जैसी स्थिति दिखने लगी है।

2016 और 2021 में टीएमसी की टिकट से वंचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम थी इसलिए विरोध व विद्रोह विकराल रूप धारण नहीं किया था। जबकि 2026 में स्थिति भिन्न है, इस दफे 4 मंत्री सहित 74 विधायकों (33 फीसदी) का टिकट कटा है।

गौरतलब है कि राज्य में 1952 में आधिकारिक तौर पर विधान परिषद का गठन किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 21 मार्च 1969 को संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। भारतीय संसद ने अनुरोध को मंजूरी दे दी और परिषद को 1 अगस्त 1969 को भंग कर दिया गया।

भाजपा में मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज बाबुल सुप्रियो पार्टी बदलकर टीएमसी का दामन थाम ममता सरकार में मंत्री बन गए थे। बाबुल सुप्रियो को मंत्रिमंडल और विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाकर राज्यसभा भेज दिया गया है। साथ ही तीन अन्य मंत्रियों को भी टिकट से हाथ धोना पड़ा है। जिन 74 विधायकों को इस दफे टिकट नहीं मिला है उनमें नामचीन लोगों में पार्थो चट्टोपाध्याय, डॉ सुदीप्तो रॉय, माणिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्ण साहा, डॉ रत्ना दे नाग, असित मजूमदार, मनोज तिवारी, विवेक गुप्ता, कृष्णेन्दू नारायण चौधरी, परेश पाल, तपन दास गुप्ता, मनोरंजन व्यापारी, कल्याण घोष, साबित्री मित्रा, कंचन मल्लिक और चिरंजीत चक्रवर्ती शामिल हैं। टीएमसी टिकट से वंचित फेहरिस्त में चर्चित शोभन चटर्जी और वैशाखी बनर्जी का भी नाम शामिल है। जिनके नामों को लेकर चर्चा व उत्सुकता दोनों ही थी। इसके अलावा सीपीएम से टीएमसी में आये प्रतिकुर रहमान, बीजेपी से टीएमसी में आई पर्णो मित्रा, पार्टी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती, ऋजु दत्तो, सुदीप्ता बख्शी, श्रावन्ति चटर्जी, इमन चक्रवर्ती और परमब्रत चट्टोपाध्याय का नाम शामिल है जिन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावना थी। 15 विधायकों का जिनका चुनाव क्षेत्र बदला गया है उनमें रत्ना चटोपाध्याय को बेहला पूर्व से बेहला पश्चिम भेजा गया है। यह शोभन चटर्जी की विवाहिता हैं और पति पत्नी में दूरी व अलगाव की वजह वैशाखी बनर्जी ही हैं। शोभन देव चट्टोपाध्याय को खरदह से बालीगंज, पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर को डेबरा से डोमकल और शौकत मोल्ला को कैनिंग से भांगड़ भेजा गया है। कैनिंग और भांगड़ दोनों ही जगह विरोध प्रदर्शन बेकाबू है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि ममता बनर्जी जब चुनाव में जेल गए नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनाएंगी तब माना जायेगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। जबकि, राशन घोटाला में जेल गए ज्योतिप्रिय मल्लिक को हाबरा और अनिसुर रहमान को देगंगा से पार्टी उम्मीदवार बनाई है। बहरहाल, ऐसा नहीं है कि किसी सियासी दल में टिकट काटे जाने का यह पहला मामला है। टिकट हमेशा बंटते-कटते रहते हैं और हर दल में होता रहा है। कुछ मामलों में जिसका टिकट काटा जाता है उनके समर्थक मौखिक या प्रतीकात्मक विरोध करते हैं। हालांकि टीएमसी के समर्थकों का विरोध कभी भी मौखिक नहीं रहा है, वो सीधे तौर पर हिंसा पर उतारू होते हुए दिखते हैं। वैसे ये विरोध पहले बीजेपी, कम्युनिस्ट या कांग्रेस के खिलाफ होता था। पर इस बार टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक ही आपस में जुझारू तौर पर लड़ते-भिड़ते दिख रहे हैं।

चौतरफा लड़ाई लड़ रहीं ममता बनर्जी के लिए ये शुभ संकेत तो नहीं ही कहा जा सकता लेकिन यह भी सच है कि ममता बनर्जी ने ही अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अराजक विचारधारा में संपोषित किया है, हिंसा के लिए उकसाया है और इन्हीं अराजक व्यवस्था के नाम पर सत्तासीन होती रहीं हैं। अब वही अराजकता इनके लिए इस बार के चुनाव से पहले ही सरदर्द बनती हुई दिख रही है। इस बार के चुनाव में असहज महसूस कर रही ममता बनर्जी के लोग ही ममता बनर्जी के खिलाफत में दिख रहे हैं और बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1. भरत चक्रवर्ती, 2. मुंबई, 3. राजस्थान, 4. 28, 5. गंगा, 6.ब्रह्मपुत्र, 7.कुतुब मीनार

संपादकीय

पश्चिम एशिया संकट : वॉशिंगटन और तेहरान की बयानबाजी से कूटनीति के लिए कम होते मौके

पश्चिम एशिया संकट के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने सप्ताहांत में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए दबाव बनाने के लिए मुलाकात की, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान दोनों की तरफ से जो बयानबाजी और सच्चाई सामने आ रही है, उससे कूटनीति के लिए कम होते मौके की ओर इशारा मिल रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने इशारा किया है कि इस्लामाबाद जल्द ही अमेरिका और ईरान के राजनयिकों की मेजबानी करने की उम्मीद कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका और ईरान के बीच बैक-चैनल बातचीत करने और संदेश भेजने के लिए चार सदस्यों की टीम बनाने की भी घोषणा की। लेकिन जब पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह ईरान का तेल लेना चाहते हैं और खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने पर विचार कर रहे हैं, जहां से ईरान अपना 90 फीसदी क्रूड निर्यात करता है। फिर, एयर फोर्स वन में सफर करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें लगता है कि शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की अगुवाई वाली कोशिशें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर ईरान के साथ जल्द ही कोई डील नहीं हुई, तो वह अमेरिकी मिलिट्री को ईरान के बिजली प्लांट, तेल के कुएं, खार्ग आइलैंड जिस पर अमेरिकी लड़ाकू विमान पहले ही एक बार बमबारी कर चुके हैं और शायद, डीसैलिनेशन फैसिलिटी (अलवणीकरण सुविधा) को उड़ाने का ऑर्डर देंगे। ट्रंप की बातचीत में भरोसा दिखाने और मिलिट्री बढ़ाने की वकालत करने के बीच बदलती पोजीशन से ऐसा लगता है कि अमेरिकी नेतृत्व उलझन में है। वे नई शांति बातचीत को भी कमजोर करते हैं, और इस शक को और पक्का करते हैं कि यह सिर्फ दिखावे की बात है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मरीन की तेजी से तैनाती और पेंटागन के जमीनी हमले की तैयारी की रिपोर्टें शांति बातचीत में मिली किसी भी तेजी को कम कर सकती हैं। पहले ही, अमेरिका ने नौ महीने के अंदर ईरान पर दो बार हमला किया है, जबकि डिप्लोमैटिक बातचीत चल रही थी। ईरान के पास वाशिंगटन पर भरोसा करने की कोई खास वजह नहीं है और देश के नेताओं और विदेश मंत्रालय ने बार-बार यह साफ किया है कि उनका मानना है कि अमेरिका जमीनी हमला करने के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। इज़राइल की उकसाने वाली हरकतें ईरानी यूनिवर्सिटी और असैन्य परमाणु ठिकानों पर बमबारी और भी ज़्यादा बिगाड़ने वाली हैं। सफल डिप्लोमेसी लगातार, पहले से पता और भरोसेमंद बातचीत पर निर्भर करती है। तेहरान के नेतृत्व से ज़्यादा, लड़ने वाले देशों के बीच सही बातचीत न होने का दोष ढुलमुल ट्रंप को देना चाहिए। सवाल है कि क्या ट्रंप के शांति के लिए राज़ी होने से पहले दुनिया को अमेरिका में युद्ध-विरोधी प्रदर्शनों के ज़ोर पकड़ने का इंतज़ार करना होगा?

"रात का सूरज" : मानव का कौशल या चमत्कार?

अब रात में भी चमकेगी सूरज की रोशनी

सुरेश सिंह बैस "शाश्वत"

मानव सभ्यता ने जब पहली बार अग्नि को साधा, तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक दिन मनुष्य स्वयं "सूरज की रोशनी" को भी अपनी सुविधा के अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। आज जब अमेरिकी कंपनी रिफ्लेक्ट आर्बिटल द्वारा उपग्रहों के माध्यम से रात में भी सूर्य जैसी रोशनी उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है। क्या यह केवल एक तकनीकी कौशल है, या सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं? इस अभिनव तकनीक का मूल सिद्धांत अत्यंत सरल लेकिन क्रांतिकारी है। सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में स्थापित दर्पणों द्वारा पृथ्वी के किसी विशेष स्थान पर परावर्तित करना। ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होंगे और इनमें लगे अत्यधिक परावर्तक पैनल सूर्य की किरणों को लक्षित क्षेत्र में भेजेंगे। यह विचार नया नहीं है, किंतु इसे व्यावसायिक स्तर पर लागू करने का साहस और संरचना देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग 2.6 लाख लोगों द्वारा इस सुविधा के लिए रुचि दिखाना इस बात का संकेत है कि मानव समाज इस संभावना को लेकर कितना उत्साहित है। यदि यह तकनीक अपने अपेक्षित स्वरूप में सफल होती है, तो इसके प्रभाव दूरगामी होंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जहां अंधेरे के कारण बाधित होने वाले राहत कार्य निरंतर जारी रह सकेंगे। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका व्यापक उपयोग संभव है, जहां समय की सीमाएं समाप्त हो सकती हैं और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। शहरी जीवन में भी यह तकनीक ऊर्जा की खपत को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था पर निर्भरता कम हो सकती है। किन्तु हर नई तकनीक अपने साथ कुछ जटिल प्रश्न भी लेकर आती है। रात का अंधकार केवल प्रकाश का अभाव नहीं, बल्कि प्रकृति का एक आवश्यक संतुलन है। अनेक जीव-जंतु और वनस्पतियां इसी प्राकृतिक चक्र पर निर्भर करती हैं, और कृत्रिम रूप से निर्मित "रात का दिन" उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी यह चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि तारों और आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए स्वाभाविक अंधकार आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या इस प्रकार की तकनीक का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा, या यह केवल कुछ विकसित देशों और संसाधन-संपन्न वर्गों तक सीमित रह जाएगी। वास्तव में यह न तो मात्र चमत्कार है और न ही केवल एक साधारण कौशल, बल्कि यह मानव बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक दृष्टि और तकनीकी नवाचार का सम्मिलित परिणाम है। यह उस दिशा का संकेत है, जहां मनुष्य केवल पृथ्वी के संसाधनों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अंतरिक्ष को भी अपने विकास के साधन के रूप में देख रहा है। भारत के संदर्भ में यह विषय केवल एक तकनीकी जिज्ञासा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, नीतिगत और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बहस का विषय बन सकता है। यदि रिफ्लेक्ट आर्बिटल जैसी तकनीक वैश्विक स्तर पर लागू होती है, तो भारत जैसे देश पर इसके प्रभाव बहुआयामी होंगे। सबसे पहले, भारत एक ऐसा देश है जहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और सौर ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में "रात में सूर्य प्रकाश" की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से सौर ऊर्जा उत्पादन को रात तक बढ़ाने में सहायक हो सकती है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय खुल सकता है। लेकिन इसके समानांतर भारत की वैज्ञानिक संरचना को भी देखना आवश्यक है। भारत ने इसरो के माध्यम से एस्ट्रोसेट और एक्सपो सेट जैसे मिशनों के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। खगोल विज्ञान के लिए स्वाभाविक अंधकार अत्यंत आवश्यक होता है, और यदि अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर परावर्तक उपग्रह स्थापित होते हैं, तो यह भारत सहित पूरी दुनिया में तारों के अध्ययन को प्रभावित कर सकता है। भारत में उत्तराखंड के देवस्थल में स्थित अंतरराष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन जैसे आधुनिक वेधशालाएं भी रात के स्वच्छ आकाश पर निर्भर हैं। इस प्रकार की कृत्रिम रोशनी उनके वैज्ञानिक अवलोकनों में बाधा बन सकती है। पर्यावरणीय दृष्टि से भारत की स्थिति और भी संवेदनशील है। यहां जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है और अनेक प्रजातियां विशेषकर पक्षी, कीट और रात्रिचर जीव प्राकृतिक दिन-रात चक्र पर निर्भर हैं। वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस प्रकार की कृत्रिम रोशनी से प्राकृतिक जैविक घड़ियां और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में "डार्क स्काई" (अंधकार संरक्षित क्षेत्र) की अवधारणा भी धीरे-धीरे विकसित हो रही है, जैसे लद्दाख क्षेत्र को डार्क स्काई रिजर्व बनाने की पहल। यदि वैश्विक स्तर पर आकाश में कृत्रिम प्रकाश बढ़ता है, तो ऐसे प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नीतिगत स्तर पर यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है। अंतरिक्ष किसी एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक साझा संसाधन है। ऐसे में यदि कोई निजी कंपनी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर प्रकाश भेजती है, तो भारत सहित सभी देशों को यह तय करना होगा कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियम, अनुमति और नियंत्रण कैसे निर्धारित किए जाएं। वर्तमान में इस क्षेत्र में स्पष्ट वैश्विक नियमन का अभाव है, जो भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण और शहरी जीवन का संतुलन अभी भी पारंपरिक प्रकृति से जुड़ा है, वहां "रात का दिन" बनना केवल सुविधा नहीं, बल्कि जीवन शैली में गहरे बदलाव का कारण बन सकता है। यह मानव स्वास्थ्य, नींद के चक्र और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार भारत के संदर्भ में यह तकनीक एक अवसर भी है और चुनौती भी। यह ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और विकास के नए द्वार खोल सकती है, परंतु साथ ही यह हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक संरचना के लिए गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। अंततः भारत जैसे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि वह इस तकनीक को केवल आकर्षण के रूप में न देखे, बल्कि विज्ञान, नीति और प्रकृति के संतुलन के साथ एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाए, ताकि प्रगति का यह प्रकाश भविष्य में किसी अंधकार का कारण न बन जाए। "रात का सूरज" एक आकर्षक और प्रेरक विचार है, जो विज्ञान कथा से निकलकर यथार्थ के करीब पहुंच रहा है। किंतु इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे किस प्रकार संतुलन, विवेक और जिम्मेदारी के साथ अपनाते हैं। यदि इसका उपयोग मानवता और प्रकृति के सामंजस्य को ध्यान में रखकर किया गया, तो यह एक वरदान सिद्ध हो सकता है; अन्यथा, यह वही रोशनी भी अंधकार का कारण बन सकती है, जिसे हम उजाले के रूप में देख रहे हैं।

रात की चादर में अब सूरज भी झांकेगा,
मानव का विज्ञान नया इतिहास बांकेगा।
पर याद रहे प्रकृति का संतुलन भी जरूरी है,
वरना उजाला ही अंधेरों का कारण आंकेगा।

जानें अपना राशिफल

मेष
फायदेमंद समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है प्रयास करे, आपसी प्रेम बनाये रखें।

वृषभ
तरक्की करने वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई विदेश में व्यापार करने पर विचार हो सकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन
खाने पीने का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं तो बीमार भी हो सकते हैं, किसी के बहकावे में आने से बचने की आवश्यकता है, बिना काम बाहर नहीं जाये, मन वश में रखें।

कर्क
काम–धन्धे वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है जो फायदेमंद होगा, आपसी प्रेम बनाये रखें, मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह
कुशलता वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य पूरा करने पर विचार हो सकता है जो सफल रहेगा, मन स्थिर रखें।

कन्या
सहायता मिलने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। प्रयास करें, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन में उत्साह रहेगा।

तुला
कठिनाई आने वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी के चक्कर में आने से नुकसान भी हो सकता है, बिना काम बाहर नहीं जायें।

वृश्चिक
हिम्मत दिखाने वाला समय हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है, अपनी बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है, आपसी प्रेम बनाये रखें।

धनु
भ्रमण करने वाला समय हो सकता है, कोई रुका हुआ सरकारी काम आगे बढ़ सकता है। प्रयास करे, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, अपने परिवार को प्रसन्न रखें, मन शान्त रखें।

मकर
परिपूर्ण समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, कोई वाहन खरिदने का विचार हो सकता है, मन में उत्साह रहेगा।

कुंभ
आशा भरा समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, जीवनसाथी पूरा साथ दे सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा।

मीन
प्रभावशाली समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किसी यात्रा पर जाने का विचार हो सकता है, मन में विश्वास रखें।

होशियार बच्चे और खोया हुआ ऊँट

एक समय की बात है, एक गांव में चार भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गाँव जा रहे थे, रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिया, जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारो भाइयों से पूछा - " मेरा ऊँट कहीं खो गया है , क्या तुम्हे आस-पास ऊँट कहीं दिखलाई दिया है?"

चारों भाई में सबसे बड़े भाई ने पुछा- " क्या ऊंट का एक पैर टूटा है?

तभी दूसरा भाई बोला- " क्या ऊंट की पूंछ कटी हुई है?"

फिर तीसरा भाई बोला- " क्या ऊंट एक आंख से काना है ?"

फिर चौथा भाई बोला- "और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं।"

बच्चों की बात सुनकर ऊँट के मालिक को लगा की अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊँट को देखा है उसने झट से बच्चों से पूछा - " बच्चो ! बतलाओ मेरा ऊँट कहाँ है।"

तभी चारो ने उत्तर दिया -" हमने ऊँट नहीं देखा । "

बच्चों की बात सुनकर ऊँट का मालिक बोला - " अगर तुमने ऊँट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा, काना, पूँछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है ?"

फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। ऊंट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊंट चुराया है। ऊँट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला- " महाराज!

मेरा ऊँट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट का हुलिया बतलाया है किन्तु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया है।"

राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं है तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम है ? तभी सबसे बड़ा भाई बोला- " महाराज ! हम जहां से जा रहे थे उस रास्तेपर ऊंट के पैरों के निशान थे, एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे बाकी तीन पैरों के निशान गहरे थे इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ था जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। "

दूसरे भाई ने कहा - " महाराज !ऊँट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहां ऊँट के पैरों के निशान थे वहां ऊंट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था इसका मतलब साफ़ था की ऊँट की पूँछ कटी हुई है इसी कारण गोबर पूँछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। "

फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा-" महाराज ! ऊंट जहां से जा रहा था वहां एक तरफ की घास तो ऊंट ने खाई थी जिसके कारण वहां घास नहीं थी और जिस तरफ ऊँट की आँख ख़राब थी वहां उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसीलिए उस तरफ ऊंट ने घास नहीं खाई थी और वहां की घास हरी थी इसीलिए हमने अंदाज लगाया कि ऊँट काना है। "

फिर चौथा भाई बोला- " महाराज ! जिस रास्ते से ऊँट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे इसलिए मैंने कहा कि ऊंट के ऊपर अनाज रखा हुआ है किन्तु हमने इनका ऊँट नहीं देखा था।"चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मण्डल में जगह दे दी।

हल करो हीरो बनो

1. भारत नाम की उत्पति का सम्बंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है?
(क) महाराणा प्रताप (ख) चन्द्रगुप्त मौर्या
(ग) भरत चक्रवर्ती (घ) अशोका मौर्या
2. भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है?
(क) मुंबई (ख) कोलकाता
(ग) दिल्ली (घ) मद्रास
3. भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है?
(क) उत्तर प्रदेश (ख) महाराष्ट्र
(ग) राजस्थान (घ) मध्यप्रदेश
4. भारत में कुल कितने राज्य है?
(क) 28 (ख) 29
(ग) 36 (घ) 15
5. भारत का सबसे लम्बी नदी कौन है?
(क) गण्डकी (ख) कोसी
(ग) ब्रह्मपुत्र (घ) गंगा
6. भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है?
(क) ब्रह्मपुत्र (ख) गोमती
(ग) गंगा (घ) चम्बल
7. भारत का सबसे ऊँची मीनार कौन है?
(क) चारमीनार (ख) कुतुब मीनार
(ग) झूलता मीनारा (घ) शहीद मीनार

(उत्तर इसी अंक में)

मार लो मुस्की

मोलू- स्कूल में गधा लेकर आ गया
टीचर- ये गधा क्यों लेकर आए हो क्लास में?
मोलू- मैम, आप ही कहती हैं कि आपने गधों को इंसान बनाया है मैंने सोचा शायद यह भी इंसान बन जाए...!!!

बीबी : लो, लाइट चली गई।
पप्पू : लाइट चली गई तो क्या, पंखा तो चालू कर।
बीबी : लो, कर दी न पागलों वाली बात, अगर पंखा चालू किया तो मोमबत्ती बुझ नहीं जाएगी...

रमेश : भाई तू कल बड़ा दुखी था।
दिपक: हां यार कल बीबी 25000 की साड़ी ले आई।
रमेश : फिर आज खुश क्यों हो।
दिपक : आज वो तेरी बीबी को दिखाने गई है।

पति ने पत्नी का फोन काटते हुए कहा मीटिंग में हूं बाद में फोन करता हूं। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फोन आया।
पड़ोसन-क्या आप फ्री हो, डिस्टर्ब तो नहीं किया?
पति-बोलिए, हुकम कीजिए।
पड़ोसन-मुझे कोई काम नहीं पर आपकी पत्नी को काम है लो बात कीजिए।
पत्नी-शाम को घर आओ तो आयोडेक्स लेते आना।

ससुर : तुम शराब पीते हो, कभी बताया नहीं।
दामाद : आपकी बेटी खून पीती है, आपने बताया था क्या?

टीचर : अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो ₹ 100 फाइन..! दूसरी बार गया तो ₹200 फाइन और तीसरी बार सीधा 500 का फाइन लगेगा..!
स्टूडेंट : सर जी ! जो हमको मंथली पास बनवाना हो तो कितने का बन जाएगा?

पति- बस मोबाइल में लगी रहा करो दाल में न नमक है न मिर्च
पत्नी- खाते वक्त तो मोबाइल छोड़ दिया करो दाल में नहीं पानी में डुबो-डुबोकर रोटी खा रहे हो।

पत्नीः शादी से पहले तो तुम मुझे होटल, सिनेमा और शॉपिंग पर ले जाते थे, अब क्या हुआ?
पतिः पगली, कभी चुनाव जीतने के बाद किसी को प्रचार करते देखा है?

गधा : मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है।
कुत्ता : तुम भाग क्यो नही जाते हो।
गधा : मालिक की खूबसूरत बेटी " जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है: "तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा बस इसी उम्मीद में टिका हूँ ।।।

माथापच्ची–23

	6			1	9			5
		3			6	7	1	
5		1			4			
						1	2	
1			8	3	2			4
	5	8						
			1			8		6
	1	9	6			2		
4			2	5			3	

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3X3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 22 का हल

3	4	6	2	5	1	9	8	7
5	2	7	6	8	9	4	1	3
9	8	1	7	3	4	6	5	2
2	7	9	3	6	8	1	4	5
1	3	5	4	9	2	8	7	6
8	6	4	5	1	7	3	2	9
7	9	2	1	4	3	5	6	8
6	1	3	8	7	5	2	9	4
4	5	8	9	2	6	7	3	1

'जल जीवन मिशन' के लिए केंद्र ने रखीं तीन नई शर्तें

पूरी नहीं हुईं तो राज्य को उठाना होगा सारा खर्च

निज संवाददाता : घरों में पीने के पानी के कनेक्शन देने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों के लिए नई शर्तें जारी की हैं। केंद्र ने कहा है कि कुछ शर्तें पूरी होने पर ही राज्य को प्रोजेक्ट का केंद्र का हिस्सा मिलेगा। नहीं तो, प्रोजेक्ट का पूरा खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया है कि यह निर्देश राज्यों को पहले ही भेज दिया गया है और उनसे तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। केंद्र ने असल में तीन शर्तें बताई हैं। पहली, राज्य को एक साफ रखरखाव नीति बनानी होगी। दूसरी, प्रोजेक्ट के वित्तीय प्रबंधन और उसे लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक एमओयू साइन करना होगा। तीसरी, हर प्रोजेक्ट की अलग से पहचान के लिए एक आईडी नंबर बनाना होगा और उसी हिसाब से खर्च का विस्तृत हिसाब केंद्र को देना होगा। ये तीन शर्तें पूरी होने पर ही केंद्र से पैसे जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2025 में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट का समय 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया था। लगभग एक साल बाद, इसी साल मार्च की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी थी। उसके बाद, ये नई शर्तें राज्यों को भेजी गईं। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने आखिरी बार अगस्त 2024 में इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य को पैसे दिए थे। अभी, यह दावा किया जा रहा है कि राज्य पर केंद्र का लगभग 7,500 करोड़ रुपये बकाया है। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में, केंद्र आमतौर पर कुल लागत का 50 फीसदी और राज्य सरकार बाकी खर्च उठाती है। हालांकि, प्रोजेक्ट शुरू करने के समय से ही एक शर्त थी- रखरखाव का खर्च राज्य को उठाना होगा। जमीन, बिजली और दूसरे ऑपरेशनल खर्च भी राज्य की जिम्मेदारी में आते हैं। नतीजतन, प्रशासनिक हलकों में नई रखरखाव नीति बनाने के आदेश को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। कई लोगों के मुताबिक, अगर यह नीति बन जाती है, तो भविष्य में प्रोजेक्ट को लागू करने का स्ट्रक्चर साफ हो सकता है।

एसएसकेएम ने कायम की मिसाल

♦ बोन बैंक से हड्डी लेकर 10 साल के लड़के के शरीर में ट्रांसप्लांट की गई

निज संवाददाता : एसएसकेएम अस्पताल के बोन बैंक से हड्डी लेकर एक नाबालिग मरीज़ के शरीर में ट्रांसप्लांट की गई। यह ट्रांसप्लांट एसएसकेएम में किया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, मरीज़ का नाम वसीम राजा (10) है। वह मुर्शिदाबाद में रहता है। राज्य में यह पहली बार है जब बोन बैंक से ली गई हड्डी किसी मरीज़ के शरीर में ट्रांसप्लांट की गई है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, वसीम कई दिनों से अपने कंधे के नीचे ट्यूमर की समस्या से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी के ज़रिए बड़े ट्यूमर को निकालना ही एकमात्र रास्ता था। ऐसे में, गैप को भरने के लिए और हड्डी की ज़रूरत थी। एसएसकेएम के एक डॉक्टर ने कहा कि एक सामान्य मरीज़ के मामले में, उसकी कमर या शरीर के किसी और हिस्से से हड्डी को रिपेयर करना मुमकिन होता। लेकिन 10 साल के वसीम के शरीर के किसी और हिस्से से और हड्डी इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। इस केस में दो ऑप्शन थे। पहला, आर्टिफिशियल (सिंथेटिक) हड्डी का इस्तेमाल करना। दूसरा, एसएसकेएम अस्पताल में कुछ महीने पहले शुरू हुए बोन बैंक से मदद लेना। मरे हुए लोगों या सर्जरी के दौरान मरीज़ के शरीर से निकाले गए हिस्सों की हड्डियों को स्टरलाइज़ करने के बाद बोन बैंक में रखा जाता है। ऐसा ही एक हड्डी का टुकड़ा, जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबा था, 11 मार्च को वसीम के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। मेडिकल भाषा में इसे एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि बोन ट्रांसप्लांट के बाद वसीम को कोई फिजिकल प्रॉब्लम (शारीरिक समस्या) नहीं हुई। सर्जरी वाली जगह पर ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल है। एसएसकेएम के डॉक्टर तन्मय दत्ता ने कहा-सर्जरी के बाद उस जगह पर कोई इंफेक्शन नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि मरीज़ जल्दी ठीक हो जाएगा।

पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात की वजह से ईंधन का संकट

खाद्य विभाग ने केरोसिन बांटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया

निज संवाददाता : पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के हालात की वजह से दुनिया भर में ईंधन सप्लाई की कमी हो गई है। इस वजह से पश्चिम बंगाल के साथ-साथ देश में भी कुकिंग गैस या एलपीजी मिलने में दिक्कतें आने लगी हैं। ऐसे में, राज्य सरकार ने आम लोगों की ऊर्जा सुरक्षा पक्का करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पर केरोसिन तेल बांटने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। केंद्र ने युद्ध के हालात को देखते हुए यह अतिरिक्त आवंटन किया है। इसमें बताया गया है कि एक एजेंट को सरकारी तेल कंपनी से कितना केरोसिन मिलेगा। हर एजेंट को करीब 12 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है। इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुल चार हजार किलोलीटर अतिरिक्त तेल आवंटन किया है। खाद्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोलियम सप्लाई में अनिश्चितता और एलपीजी संकट की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस पहल का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि लोगों, खासकर कम आय वाले और ग्रामीण इलाकों के लोगों को खाना पकाने के दूसरे ईंधन के तौर पर केरोसिन मिले। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, डिजिटल राशन कार्ड वाले हर परिवार को एक बार में 500 एमएल केरोसिन तेल दिया जाएगा। यह डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से राशनिंग सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि यह एक्स्ट्रा एलोकेशन ट्रांसपेरेंट (अतिरिक्त आवंटन पारदर्शी है) तरीके से और तय समय के अंदर पूरा करना होगा। सुपरविज़न के मामले में कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। तेल निकालने के सभी प्रोसेस 100 फीसदी होने चाहिए और अगर कोई दिक्कत आती है, तो इसकी जानकारी तुरंत ऊपर के अधिकारियों को दी जानी चाहिए। डीलरों और एजेंटों के बीच सभी ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन पूरे करने का आदेश दिया गया है, ताकि हर ट्रांज़ैक्शन का डिजिटल प्रूफ हो। इसके अलावा,डीलरों को इस खास आवंटन के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस प्रोसेस पर नज़र रखने के लिए ज़िला और सब-डिवीज़न स्तर पर खास स्क्वाड बनाने का आदेश दिया गया है। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को फिजिकली मौजूद रहकर वितरण गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। लोगों में जागरूकता लाने पर भी ज़ोर दिया गया है। हर केरोसिन डीलर को अपनी दुकानों में रखे तेल की मात्रा, तय कीमत और बांटने का रेट लोकल भाषा में साफ-साफ लिखकर टांगना होगा। रिपोर्टिंग सिस्टम को भी कड़ा कर दिया गया है। रोज़ाना तेल निकालने और सप्लाई का डेटा इकट्ठा करके हर हफ़्ते ऑफिस में जमा करना होगा। सरकार असल में इस स्थिति को युद्ध के समय की स्थिति मान रही है।इसलिए, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने या गैर-कानूनी जमाखोरी करने पर सख़्त कानूनी कार्रवाई की गई है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से आम लोगों की ईंधन की दिक्कत काफी हद तक दूर हो पाएगी। हालांकि, केरोसिन डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक गुप्ता ने कहा-डीलरों को डिमांड से बहुत कम केरोसिन तेल दिया गया है। फिर भी, जितना तेल हमें दिया गया है, हम उसी से आम लोगों की ईंधन की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि, ऐसी स्थिति में, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है।

तृणमूल की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मालदा में बदला पुलिस ऑब्जर्वर

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बिहार की एक बीजेपी नेता के पति को मालदा में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया था। चुनाव आयोग ने उन चार केंद्रों के ऑब्जर्वर बदल दिए। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा पांच और ऑब्जर्वर बदले गए हैं। मालूम हो कि जयंत कांत को मालदा के चार केंद्रों- मानिकचक, मोथाबारी, सुजापुर और वैष्णवनगर में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तृणमूल ने आरोप लगाया कि जयंत की पत्नी बिहार की बीजेपी नेता हैं। ऐसे में जयंत पश्चिम बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर की ड्यूटी बिना किसी भेदभाव के कैसे करेंगे? राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने यह सवाल उठाया था। मंत्री ब्रत्य बसु और बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक ने तृणमूल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जयंत और उनकी पत्नी की तस्वीरें जारी कीं। तृणमूल की शिकायत की जांच की गई। शनिवार को आयोग ने घोषणा की कि आईपीएस अधिकारी हृदय कांत मालदा के चार केंद्रों में पुलिस पर्यवेक्षक होंगे। वे झारखंड के निवासी हैं। हालांकि, आईपीएस हृदय बिहार कैडर के हैं। जयंत कांत के अलावा आयोग ने पांच पुलिस पर्यवेक्षकों के बदलाव की भी घोषणा की। जंगीपुर, रघुनाथगंज, सागरदिघी के प्रभारी नए पुलिस पर्यवेक्षक आए हैं। जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बाराबनी में भी नए पर्यवेक्षक दिए गए हैं। खड़गपुर सदर, पिंगला, खड़गपुर और डेबरा के प्रभारी पुलिस पर्यवेक्षकों को भी बदल दिया गया है। बागदा, बनगांव उत्तर के पुलिस पर्यवेक्षकों और हाबरा, अशोकनगर, अमडांगा के पुलिस पर्यवेक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव से पहले आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन तरह के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। इस बार हर निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 294 सामान्य पर्यवेक्षकों के साथ-साथ पुलिस पर्यवेक्षक और आय और व्यय खाता पर्यवेक्षक भी हैं। इनकी संख्या भी पहले की तुलना में बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 84 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। राज्य के 294 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे।

ईरान-यूएस युद्ध लंबा खिंचा तो हीलियम की होगी भारी कमी

भारत में नहीं हो पाएगी एमआरआई

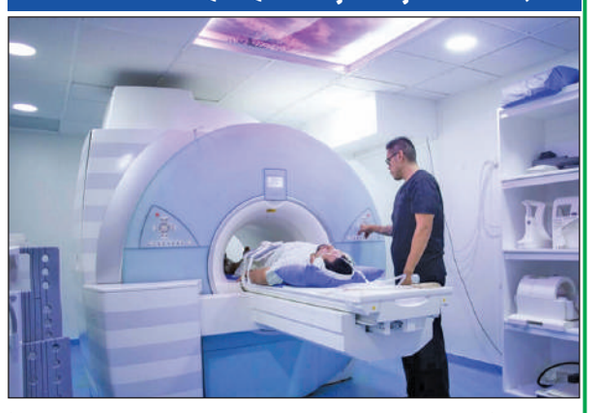

निज संवाददाता : ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने अब भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेल और एलपीजी की कीमतों में अस्थिरता के बाद अब एमआरआई मशीनों के संचालन के लिए अनिवार्य मानी जाने वाली हीलियम गैस की सप्लाई चेन बाधित होने की खबरें आ रही हैं। दरअसल, ईरान द्वारा कतर के रास लफान संयंत्र पर किए गए हमले के बाद वहां से हीलियम का उत्पादन और निर्यात प्रभावित हुआ है। भारत अपनी हीलियम संबंधी जरूरतों का 100 फीसदी आयात कतर से ही करता है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण गैस की कमी भारतीय अस्पतालों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है।

हीलियम एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जिसका तरल रूप एमआरआई मशीनों के भीतर लगे शक्तिशाली सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट शून्य से 269 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है, इसलिए यह मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य है। यदि इसकी आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है, तो पुरानी तकनीक वाली एमआरआई मशीनें बंद हो सकती हैं, जिन्हें सालाना गैस रिफिलिंग की आवश्यकता होती है। राहत की बात यह है कि राजधानी दिल्ली के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों जैसे एम्स और अन्य बड़े केंद्रों में फिलहाल सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक तकनीक वाली नई एमआरआई मशीनें अब हीलियम-फ्री या कम गैस खपत वाली हैं, जिनमें केवल स्थापना के समय ही गैस की जरूरत पड़ती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुफ्त एमआरआई सेंटर के अनुसार, उनकी मशीनें नवीनतम तकनीक पर आधारित हैं, इसलिए मरीजों को फिलहाल कोई असुविधा नहीं हो रही है। हालांकि, कुछ निजी स्कैन केंद्रों ने चिंता जताई है कि हीलियम की कमी की अफवाहों के बीच इसके दाम दोगुने हो गए हैं, जिससे आने वाले समय में एमआरआई स्कैन के खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।

वर्तमान में भारत के 60 फीसदी से अधिक एमआरआई सिस्टम ऐसी तकनीक पर आधारित हैं जिन्हें बहुत कम रखरखाव और गैस की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य का समुद्री मार्ग जल्द नहीं खुला और युद्ध लंबा खिंचा, तो सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा सकती है। ऐसी स्थिति में मरीजों के लिए डायग्नोस्टिक सेवाओं की लागत 15,000 रुपये तक बढ़ सकती है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य जगत की नजरें मध्य पूर्व के हालातों पर टिकी हुई हैं।

कस्बों और शहरों से गायब होती प्रकृति की नन्ही दूत 'गौरैया'

रमेश सर्राफ धमोरा

अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बता दें कि गौरैया की संख्या में हो रही तीव्र गिरावट के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को इन परिचित पक्षियों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके लिए हमारे आस पास का माहौल बेहतर करना है। कभी उपेक्षित समझी जाने वाली गौरैया अब कई कस्बों और शहरों से गायब हो रही हैं, जो इस दिन को रोजमर्रा की जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के प्रति चिंता का प्रतीक बनाती है। गौरैया मानव इतिहास के सबसे परिचित पक्षियों में से एक हैं। वे घरों, खेतों, बाजारों और शहरी सड़कों के पास पाई जाती हैं। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि किसी क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त भोजन, सुरक्षित घोंसले बनाने की जगह और बुनियादी पारिस्थितिक संतुलन मौजूद है। गौरैया की मधुर चहचहाहट कई देशों में सुबह और शाम के जीवन का अभिन्न अंग रही है। गौरैया छोटे, फुर्तीले पक्षी होते हैं जो 4 से 7 इंच तक लम्बे होते हैं। उनके गोल, मोटा शरीर और छोटी मजबूत चोंच होती हैं जो खुले बीजों को तोड़ने के लिए उपयुक्त होती हैं। उनके पंखों पर धारियां या गहरे रंग के धब्बे होते हैं। यह हल्की भूरे रंग या सफेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे-छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। जब बच्चा कुछ समझने लगता है तो सर्वप्रथम उसको घर के आंगन में सबसे अधिक जो पक्षी देखने को मिलता है वह नन्ही चिड़िया यानी गौरैया होती है। यह चिड़िया बचपन से ही हमारी साथी बन जाती है जो बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है और अपनी मीठी आवाज से उन्हें आकर्षित करती रहती है। गौरैया बच्चों के हाथ से कई बार खाने की वस्तु भी झपटकर ले जाती है। छोटे बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और वह फुर्र से उड़कर ऊपर बैठ जाती है। गांव देहातों में यह आज भी देखने को मिल जाता है। मगर शहरों में अब ऐसा नजारा शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। गौरैया मनुष्य के आसपास रहना पसंद करती है। यह लगभग हर तरह की जलवायु पसंद करती है पर पहाड़ी स्थानों में कम दिखाई देती है। शहरों, कस्बों, गांवों, और खेतों के आसपास यह बहुतयात से पाई जाती है। नर गौरैया के सिर का ऊपरी भाग नीचे का भाग और गालों पर पर भूरे रंग का होता है। गला चोंच और आंखों पर काला रंग होता है और पैर भूरे होते है। मादा के सिर और गले पर भूरा रंग नहीं होता है। नर गौरैया को चिड़ा और मादा चिड़ी या चिड़िया भी कहते हैं।

गौरैया पक्षियों के पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है जो विश्व के अधिकांश भागों में पाई जाती है। आरम्भ में यह एशिया, यूरोप और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती थी। लेकिन मानवों ने इसे विश्वभर में फैला दिया है। यह मनुष्यों के समीप कई स्थानों में रहती हैं। पिछले कुछ सालों में शहरों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिन्ता प्रकट की जा रही है। आधुनिक स्थापत्य की बहुमंजिली इमारतों में गौरैया को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। कभी बड़ी संख्या में हमारे साथ रहने वाली गौरैया अब धीरे-धीरे बहुत कम होती जा रही है। मगर जीवन की भाग दौड़ में किसी का ध्यान इनकी घाटी संख्या की

भारत में पक्षियों की कुल मिलाकर 1250 प्रजातियां हैं। जिनमें से 85 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जिसमें गौरैया का भी नाम शामिल है। गौरैया का सुरक्षित रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खा लेती है। जिससे किसान की फसल खराब होने से बच जाती हैं।

तरफ नहीं जा रहा है। बच्चों की सबसे नजदीकी मित्र गौरैया जिस तेजी से कम होती जा रही है उससे लगता है आने वाले समय में यह कहीं विलुप्त ना हो जाए। इसलिए हम सबको मिलकर गंभीरता से ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे गौरैया को संरक्षण मिल सके और उनकी संख्या में फिर से बढ़ोतरी प्रारंभ हो सके। गौरैया चिड़िया को घरेलू चिड़िया भी कहा जाता है। क्योंकि यह घरों के अंदर भी घोसले बनकर रह लेती है। ये मानव और प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि यह कीड़ों को खाती है जिससे कीड़े पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा धर्मशास्त्र के मुताबिक गौरैया का आपकी छत पर आना आपके लिए शुभ होता है। जानकारो का कहना हैं कि यह चिड़िया शांति और सदभावना का संदेश लेकर आती है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में घर-आंगन में चहकने-फुदकनेवाली छोटी सी प्यारी चिड़िया गौरैया की आबादी में 60 से 80 फीसदी तक की कमी आई है। ब्रिटेन की 'रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स' ने भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को 'रेड लिस्ट' में डाला था। वहीं आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक गौरैया की आबादी में करीब 60 फीसदी की कमी आई है। यह कमी ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में हुई है। पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के अनुसार गौरैया की आबादी घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जबकि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स (एसओआईबी) रिपोर्ट 2023 के मुताबिक पिछले 25 सालों में गौरैया की आबादी कुल मिलाकर काफी स्थिर रही है। हालांकि भारत में हाउस स्पैरो की संख्या कम होने की आम धारणा है। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर दिल्ली सरकार ने 2012 और बिहार सरकार ने 2013 से गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है।

कभी हमारे घर-आंगन में गिरे अनाज को खाने गौरैया फुर्र से आती थी और दाना चुगकर उड़ जाती थी। हालांकि गांवों में आज भी कई घरों में गौरैया आ रही है। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे कई कारण हैं जिन पर लगातार शोध हो रहे हैं। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे के कारणों में आहार की कमी, बढ़ता आवासीय संकट, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन-शैली में बदलाव, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जाता रहा है। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे बेतहाशा कीटनाशक का प्रयोग को माना जा रहा है। गौरैया के प्रजनन के लिए अनुकूल आवास में कमी को भी इसकी संख्या में कमी का एक कारण माना जा रहा है। कच्चे घरों का तेजी से कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होने से शहरों में इनके प्रजनन के लिए अनुकूल आवास नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि एक ही शहर के कुछ इलाकों में ये दिखती है तो कुछ में नहीं। गौरैया संरक्षण में जुड़े लोग कृत्रिम घर बनाकर गौरैया को प्रजनन के लिए आवास देने की पहल चला रहे हैं। इसमें गौरैया अंडे देने के लिए आ भी रही हैं। जहां तक गौरैया का सवाल है यह इन्सानों की दोस्त तथा किसानों की मददगार है। गौरैया इन्सान के साथ रहते हुए उन्हें सुख-शांति प्रदान करती हैं। बच्चों का बचपन इसके साथ खेलते हुए गुजरता है। लेकिन हम इन्सानो ने ही इसे अपने से दूर कर दिया है। भारत में पक्षियों की कुल मिलाकर 1250 प्रजातियां हैं। जिनमें से 85 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जिसमें गौरैया का भी नाम शामिल है। गौरैया का सुरक्षित रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खा लेती है। जिससे किसान की फसल खराब होने से बच जाती हैं। गौरैया अपना घोंसला इंसानों के करीब बनाती है। इससे उनके घोंसले उजाड़ दिए जाते हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण भी इन पक्षियों के लिए मुसीबत है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से यह समझने की कोशिश करें कि छोटी सी गौरैया हमारे जीवन के लिए कितनी अहम है। ऐसे में उसकी रक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

महानगर के छह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बनेंगे मतदान केंद्र

निज संवाददाता : चुनाव आयोग ने कहा कि कोलकाता महानगर के छह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पोलिंग स्टेशन (मतदान केंद्र) बनाए जाएंगे। इनमें छह में से चार कॉम्प्लेक्स उत्तर कोलकाता में हैं, जबकि दो दक्षिण में हैं।

उत्तर कोलकाता के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं :

* एंटाली असेंबली इलाके में एक्टिव एकड़
* सिल्वर स्प्रिंग, एंटाली
* लेक डिस्ट्रिक्ट, बेलेघाटा
* अर्जुन अपार्टमेंट, मानिकतला जिसमें दो पोलिंग स्टेशन होंगे।

दक्षिण कोलकाता में, पोलिंग स्टेशन वाले कॉम्प्लेक्स हैं :

* साउथ सिटी, रासबिहारी असेंबली इलाके में जिसमें दो पोलिंग स्टेशन होंगे
* आशा को-ऑपरेटिव, रासबिहारी

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि सिर्फ़ इन अपार्टमेंट में रहने वाले ही कॉम्प्लेक्स के अंदर बने स्टेशनों पर वोट देने के लायक होंगे। एक अधिकारी ने कहा-ये पोलिंग स्टेशन सिर्फ़ रहने वालों के लिए हैं। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता है, उसे यहां वोट देने की इजाज़त नहीं होगी। पिछले चुनावों में छह में से दो कॉम्प्लेक्स में अपनी जगह पर पोलिंग स्टेशन थे।

चुनाव आयोग ने पहले बताया था कि एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कम से कम 300 वोटर होने चाहिए और ग्राउंड फ्लोर पर एक सही कमरा होना चाहिए, तभी वह ऑन-प्रिमाइसेस पोलिंग स्टेशन (परिसर में मतदान केंद्र) के लिए क्वालिफाई कर सकता है। साउथ सिटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के सचिव देवाशीष बसु ने कहा कि साउथ सिटी के लोग पिछले कई चुनावों से साउथ सिटी इंटरनेशनल स्कूल में वोट करते आ रहे हैं। उन्होंने मेट्रो को बताया-असेंबली सीट के दो हिस्से हैं जो साउथ सिटी अपार्टमेंट के सभी वोटरों को कवर करते हैं। दोनों हिस्सों के वोटर स्कूल में अपना वोट डालते थे।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि दक्षिण कोलकाता में 412 जगहों पर 1,093 पोलिंग स्टेशन हैं, जो चार असेंबली सीटों - बालीगंज, भवानीपुर, कोलकाता पोर्ट और टॉलीगंज को कवर करते हैं। इनमें से लगभग 30 बूथ ''सेंसिटिव'' के तौर पर पहचाने गए हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा-एक सेंसिटिव बूथ पिछली घटनाओं या हिंसा, रीपोलिंग हिस्ट्री या सेक्टर अधिकारियों द्वारा नए बताए गए मुद्दों के आधार पर तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि सेंसिटिव बूथों की पहचान एक डायनामिक प्रोसेस है। उत्तर कोलकाता में, 583 जगहों पर 1,835 पोलिंग स्टेशन सात विधानसभा सीटों बेलेघाटा, चौरंगी, काशीपुर-बेलगछिया, एंटाली, श्यामपुकुर, जोड़ासांको और मानिकतला को कवर करेंगे। उत्तर कोलकाता की डीईओ स्मिता पांडे ने कहा-हमने अधिकारियों को बताया है कि इन मकसदों का कोई भी उल्लंघन करने पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।

गौरतलब है कि एक जिले में चुनाव डीईओ की देखरेख में होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं। हालांकि कोलकाता में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन दो डीईओ उत्तर और दक्षिण कोलकाता के लिए एक-ए अपने ज़ोन में चुनावों की देखरेख करते हैं।

डॉक्टरों से भी लिया जाएगा वोटिंग ड्यूटी का काम

सरकारी कर्मचारियों की कमी के मद्देनजर चुनाव आयोग का अनोखा फैसला

निज संवाददाता : हाल ही में, करप्शन के मामलों की वजह से कई सरकारी शिक्षकों की नौकरी चली गई। इस माहौल में, राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में चुनाव के माहौल में सरकारी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक अनोखा फैसला लिया है। अब से वोटिंग के लिए डॉक्टरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस माहौल में, सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों को भी प्रीसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर अपॉइंटमेंट लेटर भेजे गए हैं। इसके साथ ही, यह दावा किया गया है कि कई नौकरी खोना वाले शिक्षकों को वोटिंग ड्यूटी दी गई है। उस मामले में, चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पिछली जानकारी के मुताबिक, कुछ नौकरी खोने वाले शिक्षकों को वोटिंग ड्यूटी के लिए रखा गया होगा। पता चला है कि पिछले सोमवार को, आयोग ने आरामबाग के प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 49 डॉक्टरों को वोटिंग के काम में शामिल होने के लिए पत्र भेजे थे। इस बीच, यह डर है कि अगर डॉक्टर वोटिंग ड्यूटी करने चले गए, तो अस्पतालों में मरीज़ों की सर्विस और भी खराब हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों का प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा, अगर डॉक्टरों को वोटिंग के दौरान अपनी ड्यूटी करनी पड़ी तो स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। इससे हलचल मच गई है। हालांकि, इस माहौल में चुनाव आयोग ने कहा है कि डॉक्टरों को जिला चुनाव अधिकारियों ने वोटिंग अधिकारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही चुनाव आयोग सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी नज़र रख रहा है। इतना ही नहीं, आयोग ने कई पदों पर तबादले भी किए हैं। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी कर राज्य से 73 रिटर्निंग अधिकारियों को हटा दिया था। उनकी जगह जिन लोगों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनमें से ज़्यादातर सब-डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर या एसडीओ हैं। इससे पहले, पिछले चुनावों में आयोग राज्य के अनुरोध पर जिला एडमिनिस्ट्रेटर को ही रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता रहा है। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों में सब-डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को ही रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने वोटिंग कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद कई पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों का तबादला कर दिया था। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 15 मार्च की आधी रात से पुलिस प्रशासन में फेरबदल शुरू कर दिया था। सबसे पहले रविवार रात को राज्य के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के पदों में फेरबदल किया गया। बाद में आयोग ने राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पदों में भी फेरबदल किया। पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजी बनाया गया। और सुप्रतिम सरकार की जगह अजय नंदा कोलकाता पुलिस के नए कमिश्नर बने।फिर, इंदिरा मुखर्जी को कोलकाता के डीसी (सेंट्रल) के पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राज्य में 12 जगहों पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट भी बदल दिए। इस लिस्ट में बीरभूम, डायमंड हार्बर, पूर्व मेदिनीपुर, कूचबिहार, मालदा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं। फिर, 18 मार्च को नए निर्देश जारी किए गए और पांच डीआईजी, दो पुलिस कमिश्नर और कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हटा दिए गए। रायगंज, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, जलपाईगुड़ी और प्रेसिडेंसी रेंज के डीआईजी हटा दिए गए। 11 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हटा दिए गए। विधाननगर और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर भी हटा दिए गए। तब राज्य सरकार ने मुरलीधर शर्मा, आकाश मघारिया और इंदिरा मुखर्जी जैसे कई आईपीएस अधिकारियों को दूसरी जगह पोस्ट किया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और उन्हें दूसरे राज्यों में चुनाव देखने के लिए भेजने का आदेश दिया था।

भारत 2.0 कॉन्क्लेव में गिरीश सोडानी को मिला ''विजनरी लीडर इन फाइनेंस'' सम्मान

माहेश्वरी समुदाय का बढ़ा मान

मुंबई : वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फाइनेंस प्रोफेशनल व वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट गिरीश सोडानी को भारत 2.0 कॉन्क्लेव में ''विजनरी लीडर इन फाइनेंस'' सम्मान से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी के हाथों प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एंटरप्राइज वर्ल्ड मैगजीन द्वारा किया गया। गिरीश सोडानी को यह सम्मान निवेश परामर्श के क्षेत्र में उनके 15 वर्षों के समर्पित और प्रभावशाली योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने हमेशा निवेशकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए क्लाइंट-केंद्रित रणनीतियों को बढ़ावा दिया है। साथ ही, अनुशासित तरीके से वेल्थ क्रिएशन के महत्व को निरंतर रेखांकित किया है, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सके। उनकी कार्यशैली ने निवेशकों को न सिर्फ बेहतर और समझदारीपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में मदद की है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्थिर बनने के लिए भी प्रेरित किया है। उनकी विशेषज्ञता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। वे देश के प्रमुख बिजनेस प्लेटफॉर्म एनडीटीवी प्रॉफिट पर पैनलिस्ट के रूप में अपनी बाजार संबंधी समझ और विश्लेषण साझा करते रहे हैं। वहीं, 40 वर्ष की आयु से पहले राष्ट्रीय मंच पर यह सम्मान प्राप्त करना उनकी पेशेवर यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अपनी इस उपलब्धि पर सोडानी ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए एक अविस्मरणीय उपलब्धि है, जिसने उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर नई प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें निवेशकों को जागरूक बनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के अपने मिशन को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। वित्तीय क्षेत्र में तेजी से बदलते परिदृश्य के बीच, गिरीश सोडानी की यह उपलब्धि युवा निवेशकों और उभरते पेशेवरों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरी है।

महिला वोट बैंक के सहारे यूपी की सत्ता में वापस लौटने की जुगत में अखिलेश

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ वाले महिला वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी की नजर लग गई है। पीडीए-पीडीए करते-करते सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश की उन महिलाओं को लुभाने में लग गए हैं, जो अखिलेश यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा डरी सहमी रहती थी। इसी को मुद्दा बनाकर 2017 में बीजेपी ने यूपी में सत्ता हासिल की थी। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगीराज में महिलाएं अपने आप को समाजवादी सरकार के समय से ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। इस बात का प्रमाण है भाजपा को मिलने वाला महिलाओं का वोट। महिला वोटर खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह समाजवादी सरकार के समय महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार है। खैर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब अखिलेश यादव को महिलाओं के सम्मान की चिंता सताने लगी है। लखनऊ में बीते 22 मार्च को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जब महिलाओं का सम्मान समारोह शुरू हुआ तो माहौल एकदम अलग था। अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली सैकड़ों महिलाओं को माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने साफ कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनी तो नारी समृद्धि सम्मान योजना शुरू होगी और इसके तहत गरीब परिवार की हर महिला को सालाना 40 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। साथ ही पुरानी समाजवादी पेंशन योजना को भी नई रूप में बहाल किया जाएगा। यह घोषणा महज कोई वादा नहीं बल्कि सपा की नई चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है जिससे आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को लक्ष्य बनाया गया है। वैसे बता दे इस तरह के दावे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में भी कर चुके हैं लेकिन महिला मतदाताओं ने उन पर विश्वास नहीं किया।

दरअसल, अखिलेश यादव पिछले कई सालों से सत्ता वापसी की कोशिश में लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 के लिए उन्होंने उस फॉर्मूले में एक और अक्षर जोड़ दिया है। वह है ए यानी आधी आबादी। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि पीडीए के साथ ए को जोड़कर महिला सशक्तिकरण को चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पुरानी योजनाओं का भी जिक्र किया। 1090 हेल्पलाइन हो या मुलायम सिंह यादव कन्या विद्याधन योजना और रानी लक्ष्मीबाई योजना इन सबको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सपा हमेशा महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से तय होती है। अगर स्त्रियों की स्थिति की जानकारी हो जाए तो पूरे समाज की तस्वीर साफ हो जाती है। कार्यक्रम का नाम रखा गया था मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह। मूर्ति देवी अखिलेश यादव की दादी और मुलायम सिंह यादव की मां थीं जिन्होंने मुलायम सिंह को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का संस्कार दिया। वहीं मालती देवी मुलायम सिंह की पत्नी और अखिलेश की मां थीं जिन्होंने घर संभालकर पति को राजनीति के लिए पूरी आजादी दी। अखिलेश ने इन दोनों विभूतियों को याद करते हुए कहा कि इन्हीं संस्कारों के चलते वह आज इस मुकाम पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें ऐसी कोई वीरांगना या सामाजिक आंदोलन चलाने वाली क्यों नहीं देखी जो उसके परिवार से इतर हो। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस मौके पर कहा कि देश को आगे बढ़ना है तो महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने चिंता जताई कि नई पीढ़ी की बेटियां कुछ पीछे छूटती जा रही हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। अगर कैमरे अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो सत्ता परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। उन्होंने डायल 100 की पुरानी व्यवस्था का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने जानबूझकर वहां महिलाओं को रखा था क्योंकि वे दुख और तकलीफ को बेहतर समझती हैं। आने वाले समय में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर नई योजना लाकर महिलाओं को और सम्मान दिया जाएगा। बहरहाल इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने अखिलेश सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को बड़ा मुद्दा बनाया था। तब एंटी रोमियो स्क्वायड जैसी पहल के साथ योगी सरकार ने इस वर्ग का विश्वास जीता। पिछले सालों में एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जैसी नीतियों ने अपराधियों पर लगाम लगाई और महिलाओं को भयमुक्त माहौल देने का दावा किया गया। लेकिन

दिया आधी आबादी के कल्याण का नारा

अखिलेश अब कह रहे हैं कि मौजूदा समय में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर और दूसरे जिलों में घट रही घटनाओं का भी जिक्र किया जहां पुलिस पर दबाव का आरोप लगाया। उनका तर्क है कि आर्थिक मदद के साथ सुरक्षा का माहौल भी जरूरी है और यही कमी पूरी करने के लिए नारी समृद्धि योजना लाई जा रही है। इस घोषणा का असर देखने के लिए बिहार का उदाहरण सामने है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रुपये का कारोबार शुरू करने के लिए मदद देने का ऐलान किया। राशि सीधे खातों में पहुंची और महिला वोट बैंक ने एनडीए को बड़ा समर्थन दिया। यूपी में भी योगी सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं लेकिन अखिलेश ने सीधे नकद 40 हजार रुपये सालाना देने का वादा कर बड़ा दांव खेला है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि सपा शासन में महिलाएं सुरक्षित रहीं और अब आर्थिक मजबूती से वे और मजबूत होंगी। उनका दावा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए महिलाएं सपा के साथ तेजी से जुड़ रही हैं।

दरअसल, अखिलेश यादव पिछले कई सालों से सत्ता वापसी की कोशिश में लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 के लिए उन्होंने उस फॉर्मूले में एक और अक्षर जोड़ दिया है। वह है ए यानी आधी आबादी। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि पीडीए के साथ ए को जोड़कर महिला सशक्तिकरण को चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा।

दूसरी ओर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का मतलब ही महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से लेकर 2022 तक हर चुनाव में आधी आबादी ने सपा को उखाड़ फेंका। 2024 में कुछ सीटें ज्यादा जीतने का श्रेय धोखे को दिया और कहा कि 2027 में सपा का पूरा सफाया होगा। मौर्य ने आगे कहा कि कोई अपना सुहाग संतान या राखी खतरे में नहीं डालेगा। सपा के पास गुंडे माफिया अपराधी और भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज है। इसलिए सपा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का हाल वही है जो सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उनके शासन में बहन बेटियां सहमी हुई थीं और नारा लगता था देख सपाई बिटिया घबराई। बहू बेटियों की आबरू लूटी जाती थी और निकलना दूभर था। वे मुंबई से डांस करने वालियां बुलाते थे और अब महिला सम्मान की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगे भी बेहतर योजनाएं लाई जाएंगी। हर बच्ची युवती और नारी को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाई जाएगी। उन्होंने सपा के संकल्प को दोहराया कि प्रदेश की संपूर्ण उन्नति तभी संभव है जब महिलाएं मजबूत हों। इस बीच ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी दलों ने भी कटाक्ष किया है कि ना नौ मन गेहूं होई ना राधा नाचेगी। लेकिन सपा का फोकस साफ है। वह महिला वोट को जोड़कर 2027 में वापसी का सपना देख रही है।

अब सवाल यह है कि यह वादा जमीनी स्तर पर कितना असरदार साबित होगा। महिलाएं न सिर्फ आर्थिक मदद चाहती हैं बल्कि सुरक्षा सम्मान और बेटियों की बेहतर शिक्षा भी चाहती हैं। सपा ने इन सबको जोड़ने की कोशिश की है। भाजपा की ओर से भी महिलाओं के लिए योजनाएं जारी हैं लेकिन सपा का यह सीधा नकद हस्तांतरण वाला मॉडल नया है। बिहार में कामयाब रहा तो यूपी में भी असर दिख सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा भारी पड़ता है। 2017 में यही मुद्दा सपा की हार का बड़ा कारण बना था। अब 2027 में दोनों पार्टियां इस मोर्चे पर आमने सामने हैं। कार्यक्रम में सम्मानित महिलाओं में खेल शिक्षा चिकित्सा पर्यावरण और किसान क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल थीं। यह दिखाता है कि सपा हर क्षेत्र की महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर सत्ता आई तो पहले से बेहतर काम करेंगे। उनकी पार्टी का दावा है कि महिलाएं अब बदलाव चाहती हैं और वोट के जरिए वह बदलाव लाएंगी। दूसरी तरफ भाजपा का तर्क है कि सपा का राजनीतिक सूर्य अस्त हो चुका है और 2047 तक भी उम्मीद नहीं। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह महिला केंद्रित हो गई है। अखिलेश यादव का यह दांव 2027 के चुनावी मैदान को और रोचक बना रहा है। देखना होगा कि महिला वोट बैंक किसके पक्ष में झुकता है। क्या 40 हजार रुपये का वादा पुरानी यादों को मिटा पाएगा या कानून व्यवस्था की बात फिर भारी पड़ेगी। फिलहाल राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और दोनों पक्ष अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूपी की महिलाएं इस बार तय करेंगी कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए।

कांग्रेस ने चला दलित-आदिवासी-मुस्लिम कार्ड

- बंगाल की सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव
- उम्मीदवारों की सूची में अधीर रंजन व मौसम नूर

निज संवाददाता : कांग्रेस ने 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के दो फेज में होने वाले चुनावों के लिए अपने 284 उम्मीदवारों की लिस्ट बीते रविवार को जारी की, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और पूर्व लोकसभा सदस्य मौसम बेनजीर नूर को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने राज्य की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, हालांकि रविवार को 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अनूसूचित जाति के 68 और अनुसूचित जनजाति के 16 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, अब तक 67 मुस्लिमों को टिकट दिया है और कुल कुल 72 को देना तय हुआ है। इसी तरह से कुल 44 महिलाओं को टिकट देना तय हुआ है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने 2021 के विधानसभा चुनाव सहयोगी के तौर पर लड़े थे, लेकिन किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने 1999 से मुर्शिदाबाद जिले की बरहमपुर लोकसभा सीट से पांच बार जीत हासिल की है, हालांकि 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार गए थे। इस हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बहरामपुर से 5 बार के सांसद और पूर्व नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को विधानसभा उम्मीदवार बनाया है, जो उनकी पुरानी लोकसभा सीट के तहत आता है। वहीं, मौसम बेनजीर नूर, जिन्होंने 2009 और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मालदा उत्तर लोकसभा सीट जीती थी, मालदा जिले के मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगी। वह 2019 में टीएमसी में शामिल हुईं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खगेन मुर्मू से हार गईं। नूर, जिन्हें टीएमसी ने राज्यसभा सदस्य बनाया था, इस साल जनवरी में कांग्रेस में वापस आ गईं और संसद से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने सियासी संकेत दिया है। लिस्ट में रोहन मित्रा का भी नाम है, जो दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा के बेटे हैं और सबसे लंबे समय तक राज्य अध्यक्ष रहे हैं और वे दक्षिण कोलकाता के बालीगंज से चुनाव लड़ेंगे। भले ही हुमायूं कबीर-ओवैसी गठजोड़, लेफ्ट, कांग्रेस के बीच मुस्लिम मतों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक की सदस्य टीएमसी को नजरंदाज किया और इस तरह कांग्रेस बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है।

वेष नहीं, गुणों से पहचाने जाते हैं संत

डा. पंकज भारद्वाज

भारत की संत परंपरा अत्यंत गौरवशाली रही है। कुछ व्यक्तियों के आचरण के कारण संपूर्ण संत समाज को संदेह की दृष्टि से देखना उचित नहीं। साथ ही, विवेकपूर्ण दृष्टि रखना भी समाज का दायित्व है।

इस समय भारतीय समाज में एक अलग तरह की बहस छिड़ गयी है जिसमें असली संत बनाम नकली संत को लेकर सभी के अपने-अपने तर्क दिखाई पड़ रहे हैं। किन्तु हमारे धार्मिक ग्रंथों में संत की न केवल महिमा बताई गयी वरन् संत के लक्षण तक बताए गये हैं।

भारतीय सनातन परंपरा में संतों का स्थान अत्यंत उच्च और पूजनीय माना गया है। संत केवल धार्मिक आचार्य नहीं, बल्कि समाज के नैतिक मार्गदर्शक होते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में संतों के स्वरूप, गुण और महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है।

रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं-

''संत हृदय नवनीत समाना।
कहा कबिन्ह पर कहइ न जाना।।''

अर्थात् संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। वे दूसरों के दुःख से द्रवित हो जाते हैं और किसी के प्रति कठोरता नहीं रखते। आगे तुलसीदास जी संत और असंत के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-

''बंदउं संत असज्जन चरना।
दुःखप्रद उभय बीच कछु बरना।।''

यहां संत और असंत दोनों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए विवेकपूर्ण दृष्टि रखने की प्रेरणा दी गई है।

इसी प्रकार भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण सज्जनों और संतों की रक्षा का आश्वासन देते हैं-

''परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।।''
(अध्याय 4, श्लोक 8)

अर्थात् सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए भगवान युग-युग में अवतार लेते हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि संत समाज में धर्म और नैतिकता के संवाहक होते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में संत के लक्षणों का वर्णन मिलता है-

''तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्।
अजाता-शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः।।''

अर्थात् सच्चे साधु सहनशील, दयालु, सबके हितैषी, शत्रुता से रहित और शांत स्वभाव के होते हैं। यही उनके वास्तविक आभूषण हैं।

यदि हम हनुमान चालीसा का स्मरण करें तो उसमें संतत्व के गुणों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है-

''विद्यावान गुणी अति चातुर।
राम काज करिबे को आतुर।।''

यहां ज्ञान, गुण, विनम्रता और सेवा भाव चारों का सुंदर समन्वय है। हनुमान जी अपार बलशाली होते हुए भी अत्यंत विनीत और समर्पित रहे। यही संतत्व का मर्म है शक्ति के साथ नम्रता और सामर्थ्य के साथ सेवा।

वर्तमान समय में जब समाज में ''असली संत बनाम नकली संत'' की चर्चा होती है, तब आवश्यक है कि हम संत के शास्त्रीय लक्षणों को आधार बनाएं। संतत्व वस्त्रों से नहीं, बल्कि आचरण से प्रकट होता है। जहां करुणा, सत्य, संयम और सेवा का भाव है, वहीं संतत्व है। वहीं यदि अहंकार, स्वार्थ या विभाजन की भावना दिखाई दे, तो समाज को सजग रहना चाहिए परंतु बिना किसी के प्रति कटुता या पूर्वाग्रह के।

आईएमएफ की चेतावनी.....

(प्रथम पृष्ठ का शेषांश)

इसका असर भविष्य में फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है और इससे खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति उन देशों के लिए विशेष रूप से गंभीर हो सकती है, जहां लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। वास्तव में, कम आय वाले देशों में, परिवार अपने बजट का लगभग 36 फीसदी भोजन की चीजों पर खर्च करते हैं, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा लगभग 9 फीसदी है। नतीजतन, भोजन की कीमतों में वृद्धि इन देशों में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। आईएमएफ ने कहा कि यदि स्थिति बिगड़ती है, तो कई देशों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि यह संकट वैश्विक स्तर पर महंगाई को फिर से बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। कीमतों में वृद्धि की लंबी अवधि महंगाई की उम्मीदों को अस्थिर कर सकती है, जिससे वेतन और कीमतों के बढ़ते चक्र को शुरू होने का जोखिम बढ़ जाता है। आईएमएफ के अनुसार, इस संकट का अंतिम प्रभाव संघर्ष की अवधि पर निर्भर करेगा। अगर यह कम समय तक रहता है, तो नुकसान सीमित हो सकता है। हालांकि, अगर यह लंबे समय तक जारी रहता है या बढ़ता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका लग सकता है। फिलहाल, आईएमएफ ने स्पष्ट किया है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपनी आने वाली रिपोर्टों में एक विस्तृत आकलन पेश करेगा। आईएमएफ का संदेश साफ है कि यह संकट भले ही क्षेत्रीय हो, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे, और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को पर इसका ज्यादा असर होगा। फिलहाल, आईएमएफ ने स्पष्ट किया है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपनी आने वाली रिपोर्टों में एक विस्तृत आकलन पेश करेगा। आईएमएफ का संदेश साफ है कि यह संकट भले ही क्षेत्रीय हो, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे, और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को पर इसका ज्यादा असर होगा।

अजब-गजब

दो भाइयों ने रूबिक्स क्यूब सुलझाने का तोड़ दिया पुराना विश्व रिकॉर्ड

निज संवाददाता : रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस के अपने जुनून को मिलाकर ब्रिटेन के दो भाइयों ने ऐसा रोबोट तैयार किया है, जिसने रूबिक्स क्यूब सुलझाने का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोबोट 'द रिवेंजर' ने 4 गुणा 4 गुणा 4 रूबिक्स क्यूब को महज 45.30 सेकंड में हल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैथ्यू पिडेन और थॉमस पिडेन द्वारा बनाए गए इस रोबोट की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड वर्ष 2014 में 1 मिनट 18.68 सेकंड का था, जिसे इस रोबोट ने लगभग 33 सेकंड पहले ही पीछे छोड़ दिया। यह रिकॉर्ड प्रयास मई 2025 में किया गया था, जिसकी आधिकारिक पुष्टि बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने की। दोनों भाइयों ने इस परियोजना को तकनीकी कौशल और टीमवर्क के जरिए साकार किया। मैथ्यू पिडेन ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं और उन्होंने इस रोबोट को अपने अंडरग्रेजुएट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करना शुरू किया था। उन्होंने मात्र 15 सप्ताह के भीतर रोबोट की डिजाइनिंग, निर्माण और ट्यूनिंग पूरी कर ली। इस दौरान उनके भाई थॉमस पिडेन ने प्रोडक्ट डिजाइनर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रोबोट के हार्डवेयर व डिजाइन को बेहतर बनाने में योगदान दिया। 'द रिवेंजर' में दो वेबकैम लगाए गए हैं, जो कंप्यूटर विजन तकनीक की मदद से रूबिक्स क्यूब के सभी हिस्सों को स्कैन करते हैं। रोबोट में चार मैकेनिकल आर्म्स हैं, जो क्यूब को घुमाने और सही दिशा में मोड़ने का काम करते हैं। स्कैन से प्राप्त डेटा को एक कस्टम एल्गोरिदम लैपटॉप पर प्रोसेस करता है और क्यूब को सबसे तेज तरीके से हल करने का समाधान निकालता है। रिकॉर्ड प्रयास के दौरान कैमरों को प्लास्टिक शटर से ढक दिया गया था ताकि शुरुआत से पहले क्यूब के किसी भी हिस्से को देखा न जा सके और पूरा प्रयास पूरी तरह स्वचालित बना रहे। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान रोबोट ने कुल छह प्रयास किए। पहले दो प्रयास असफल रहे, लेकिन तीसरे प्रयास में ही उसने 53 सेकंड में पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बावजूद दोनों भाइयों को विश्वास था कि इससे भी बेहतर समय हासिल किया जा सकता है। अंततः छठे प्रयास में रोबोट ने 45.30 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। जैसे ही क्यूब के सभी फेस एक ही रंग में बदल गए, वहां मौजूद दर्शकों ने तालियों से इस उपलब्धि का स्वागत किया। मैथ्यू पिडेन ने बताया कि बचपन से ही उन्हें रूबिक्स क्यूब और कंप्यूटर साइंस दोनों में दिलचस्पी थी, इसलिए दोनों को जोड़कर यह प्रोजेक्ट बनाना स्वाभाविक लगा।

बिना रुके पूरी की 13,560 किलोमीटर की उड़ान!

नन्हे 'बाहुबली' ने दिखाया कारनामा

निज संवाददाता : क्या कोई बिना कुछ खाए-पिए, एक पल के लिए रुके बगैर लगातार 11 दिनों तक आसमान में उड़ सकता है? इंसान तो छोड़िए हवाई जहाजों भी इतने लंबे सफर में संघर्ष कर देंगे, लेकिन प्रकृति के एक नन्हे 'बाहुबली' ने यह कारनामा कर दिखाया है। 'बी6' नाम के एक चार महीने की पक्षी ने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तक 13,560 किलोमीटर की लगातार उड़ान भरकर पूरी दुनिया और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। यह चमत्कारी पक्षी बार-टेल्ड गॉडविट प्रजाति का है। यह अपने लंबे प्रवासी सफर के लिए दुनियाभर में मशहूर है। जब इसने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साल 2022 में, तब इसकी उम्र महज चार महीने थी। एक सर्वे ने इस पक्षी पर एक सैटेलाइट टैग लगाया था, जिसके जरिए इस ऐतिहासिक उड़ान को ट्रैक किया गया। आमतौर पर यह प्रजाति आर्कटिक क्षेत्रों अलास्का और साइबेरिया में प्रजनन करती है और सर्दियों में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का रुख करती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का से न्यूजीलैंड का इनका आम रास्ता करीब 11,000 किलोमीटर का होता है, जिसे ये बिना रुके 9 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन बी6 ने प्रशांत महासागर के ऊपर से 13,560 किलोमीटर उड़कर जानवरों की दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उड़ान के दौरान इनकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरते हुए इस पक्षी के पास न तो आराम करने के लिए कोई जमीन थी और न ही खाने-पीने का कोई साधन। इस 'सुपर-मैराथन' के लिए बी6 ने अलास्का में जमकर दावत उड़ाई और इतना खाया कि इसका आधा वजन केवल चर्बी का हो गया। उड़ान के दौरान वजन कम करने और ऊर्जा बचाने के लिए इस पक्षी ने अपने शरीर के अंदरूनी अंगों को सिकोड़ कर छोटा कर लिया। यह अनोखी तरकीब उसे जमा की गई चर्बी को कुशलता से बर्न करने में मदद करती रही। इतने विशाल महासागर के ऊपर जहां कोई रास्ता नहीं होता, वहां भटके बिना सीधा तस्मानिया कैसे पहुंचा जा सकता है? इसका जवाब है पक्षी का इन-बिल्ट नेविगेशन सिस्टम! बी6 ने धरती के चुंबकीय क्षेत्र को एक प्राकृतिक कंपास की तरह इस्तेमाल किया। इसकी आंखों में 'क्रिप्टोक्रोम' नाम के खास प्रोटीन होते हैं, जो इन चुंबकीय क्षेत्रों को भांप लेते हैं। इसके अलावा ये पक्षी तारों, सूरज की स्थिति और यहां तक कि गंध का भी इस्तेमाल नेविगेट करने के लिए करते हैं। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 11 दिनों तक बिना रुके यह पक्षी सोया कैसे? दरअसल, ये हवा में उड़ते हुए ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। इसे 'यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप' कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पक्षी के दिमाग का आधा हिस्सा सो जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा उड़ने के लिए पूरी तरह अलर्ट रहता है यानी 'एक आंख खोलकर सोना'। ऊर्जा बचाने के लिए ये इलाके के हिसाब से अपनी ऊंचाई भी बदलते रहते हैं। गर्म रेगिस्तानों के ऊपर ये ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि ठंडे रहें और पानी के ऊपर हवा के बहाव का फायदा उठाने के लिए नीचे उड़ते हैं।

वण्य-जीव

कुनों के चीते और बंगाल टाइगर

रफ्तार व स्वभाव में दोनों हैं अलग-अलग

निज संवाददाता : हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी सामने आई थी। नामीबिया से भारत लाई गई मादा चीता ज्वाला ने पांच शावकों को जन्म दिया था। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई। चीतों की कम आबादी पर कुछ लोग चिंता भी व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत बंगाल टाइगर की संख्या कितनी है और इन साधारण टाइगर और बंगाल टाइगर में कौन ज्यादा खतरनाक होता है। कूनो नेशनल पार्क में पांच शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। भारत में लगभग 70 साल बाद चीतों की वापसी प्रोजेक्ट चीता के तहत की गई। यह देश में चीतों की पुनर्वापसी की बड़ी सफलता मानी जा रही है। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीते को देश में विलुप्त घोषित किया था। लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की अनुमति दी थी। सितंबर 2022 में पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा बाद में 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। अब नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या 50 पार हो गई है। भारत सरकार द्वारा साल 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में बंगाल टाइगर की संख्या 3,682 है। हालांकि 4 साल बाद स्थिति क्या इसका आंकड़ा अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। लेकिन कयास जताए जा रहे हैं कि बाघों का आबादी सालाना 6 फीसदी की दर से बढ़ रही हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया के लगभग 75 फीसदी बाघों का घर है। 2006 में भारत में इन टाइगरों की संख्या 1411 थी, जो अब तेज गति से बढ़ रही है। 60 के दशक में भारत में चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था, वर्तमान में इनकी संख्या 53 है, जबकि बंगाल टाइगर की संख्या करीब 3,167 है। अगर रफ्तार की बात करें को चीता से रेस में जंगल का राजा शेर भी आगे नहीं भाग सकता है। चीते की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। वहीं बंगाल टाइगर की रफ्तार महज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी रफ्तार में चीता बंगाल टाइगर से दोगुना आगे है। बंगाल टाइगर का वजन करीब 200 से 300 किलोग्राम होता है। वह आसानी से इंसानों भैंसा, हिरण जैसे बड़े जानवरों का शिकार कर सकता है। साथ ही इंसानों पर भी हमले के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं चीता का वजन 35 से 65 किलोग्राम का होता है। लेकिन बंगाल टाइगर की तुलना में इसके जबड़े, पंजे और मसल पावर ज्यादा मजबूत होती है। यानी सीधे मुकाबले में बंगाल टाइगर आसानी से चीता को चित कर सकता है।

कल्पना चावला: दुनिया के लिए बन गई मिसाल

अंतरिक्ष विज्ञान

निज संवाददाता : पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का 17 मार्च को जन्म हुआ था। अपने घर में कल्पना सबसे छोटी थीं, लेकिन उनके काम इतने बड़े हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गईं। वह भारत की पहली ऐसी महिला थीं, जिन्होंने स्पेस में जाकर इतिहास रच दिया था। जन्म और शिक्षाहरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। उन्होंने करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन से शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की पढ़ाई की थी। फिर वह एम.टेक की पढ़ाई के लिए अमेरिका गईं। बाद में कल्पना चावला ने वहीं शादी कर ली थी। साल 1995 में कल्पना चावला नासा में बतौर अंतरिक्ष यात्री शामिल हुई थीं। फिर साल 1998 में कल्पना को पहली बार उड़ान के लिए चुना गया था। उनकी यह यात्रा सफल रही और भारत की इस बेटी ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया।दूसरी बार उन्हें फिर चुना गया। सभी लोग बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन खबर कुछ ऐसी आई कि सबके चेहरों पर खुशी की जगह आंसू छलक आए। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उसकी उष्मारोधी परतें फट गई और यान का तापमान बढ़ने से यह हादसा हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थीं। 1 फरवरी 2013 में जिस अंतरिक्ष यान से वह लौट रही थीं उस यान में कल्पना चावला सहित 7 लोग सवार थे। इन में सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। यान कोलंबिया शटल एसटीएस-107 करीब दो लाख फीट की ऊंचाई पर था। इसकी रफ्तार करीब 20 हजार किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह यान 16 मिनट बाद पृथ्वी पर उतरने ही वाला था लेकिन तभी यह हादसा हो गया जिसमें सभी की मौत हो गई।

तेलंगाना में खुदाई के दौरान सामने आया 12वीं सदी से जुड़ा इतिहास

निज संवाददाता : तेलंगाना राज्य के भूपालपल्ली जिले में एक महत्वपूर्ण खोज ने इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया है। कटारम मंडल के चिंथकानी गांव के नजदीक एक नदी में भगवान विष्णु की एक प्राचीन पत्थर की बनी मूर्ति मिली है। जानकारों का मानना है कि यह मूर्ति 12वीं शताब्दी की और काकतीय काल की जटिल शिल्पकारी को दर्शाती है। नदी के किनारे स्थित जंगल क्षेत्र में एक छोटी खुदाई के दौरान यह दुर्लभ मूर्ति मिली है। संस्कृति एवं विरासत अनुसंधान दल के सचिव अरविंद पाकिदे ने बताया कि, यह मूर्ति 12वीं शताब्दी की है। खास बात यह है कि किले के समीप हाल ही में विष्णु मूर्ति की एक उत्कृष्ट नक्काशीदार प्रतिमा मिली है। शैली और प्रतिमा के नजरिए से इस मूर्ति को काकतीय काल के समय का माना जा सकता है, जो उस समय के उच्च स्तर की शिल्प कौशल को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि, मूर्ति कई भागों में क्षतिग्रस्त है। विरासत संरक्षण के नजरिए से मूर्ति को तेलंगाना विरासत विभाग द्वारा औपचारिक रूप से दस्तावेजीकृत और संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि इसे और खराब होने से बचाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि, करीब तीन साल पहले जब नदी का जलस्तर कम हुआ था, तब स्थानीय लोगों ने मदराम गांव के नजदीक पेद्दावागु धारा की रेत में मूर्ति का सिर वाला हिस्सा देखा था। उस वक्त किसी ने इसे नदी से बाहर नहीं निकाला था, इसलिए यह दबा

♦ नदी में दबी मिली 5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति

ही रहा। हाल ही में जब नदी में पानी का जलस्तर कम हुआ तो पूरी मूर्ति दिखाई देने लगी। तेलंगाना राज्य पुरातत्व विभाग के सहायक निदेशक डी.बुज्जी ने बताया कि, हमें सूचना मिली है कि कटारम मंडल में स्थानीय लोगों को भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। हम घटनास्थल का दौरा करेंगे, मूर्ति की जांच करने के बाद इसे स्थानांतरित करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, काले ग्रेनाइट से तराशी गई यह मूर्ति करीब 5 फीट ऊंची है। हालांकि नाक और उंगलियां थोड़ी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन इसका ज्यादातार हिस्सा अक्षुण्ण है। इस खोज से तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश पड़ता है और यह पता चलता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन कलाकृतियों का संरक्षण क्यों जरूरी है।

दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में: लैंसेट रिपोर्ट

निज संवाददाता : दुनियाभर में हर साल लाखों महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी वजहों से जान गंवा रही हैं, और इन आंकड़ों में भारत की हिस्सेदारी अब भी बड़ी बनी हुई है। हाल ही में द लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, और महिला स्वास्थ्य में प्रकाशित एक स्टडी ने इस चिंता को फिर सामने ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में दुनिया भर में करीब 2.4 लाख महिलाओं की मौत गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी दिक्कतों के कारण हुई। इनमें से लगभग 24,700 मौतें भारत में दर्ज की गईं। यानी वैश्विक स्तर पर हर 10 मातृ मौतों में से लगभग एक भारत से जुड़ी है, जो स्थिति की गंभीरता को दिखाती है। हालांकि, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। बीते तीन दशकों में भारत ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है। 1990 में जहां मातृ मृत्यु का आंकड़ा करीब 1.19 लाख था, वह 2015 तक घटकर 36,900 और 2023 में 24,700 तक पहुंच गया। इसी तरह, मातृ मृत्यु दर 1990 में 508 से घटकर 2023 में 116 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सुधार अभी अधूरा है। डॉ. आभा मजूमदार ने बताया कि देश में मातृ मृत्यु दर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन यह सभी राज्यों में समान नहीं है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य वर्ल्ड मानकों के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। स्टडी में यह भी सामने आया कि मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण अब भी वही हैं, जिन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है। इनमें प्रसव के दौरान अत्यधिक ब्लड फ्लो, हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतों, और इंफेक्शन पहले से मौजूद बीमारियों के कारण होने वाली दिक्कतें शामिल हैं।

रहस्य, आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम

कैलाश पर्वत और संभला लोक

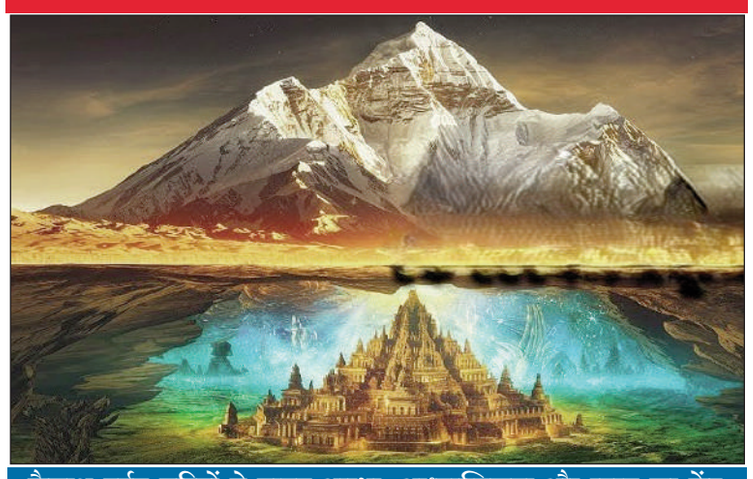

कैलाश पर्वत सदियों से मानव आस्था, आध्यात्मिकता और रहस्य का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि अनेक धर्मों और परंपराओं में दिव्य ऊर्जा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है।

निज संवाददाता : हिमालय की विशाल विराट पर्वत मालाओं के मध्य स्थित कैलाश पर्वत सदियों से मानव आस्था, आध्यात्मिकता और रहस्य का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि अनेक धर्मों और परंपराओं में दिव्य ऊर्जा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए कैलाश पर्वत अत्यंत पवित्र स्थल है। इसी पर्वत से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी अवधारणा है-''संभला लोक'' या शम्भाला, जिसे कई परंपराओं में एक दिव्य और गुप्त आध्यात्मिक राज्य माना गया है। प्राचीन भारतीय और तिब्बती परंपराओं में वर्णित शम्भाला को एक ऐसे आध्यात्मिक लोक के रूप में देखा जाता है जो सामान्य मानव दृष्टि से अदृश्य है। मान्यता है कि यह स्थान अत्यंत विकसित आध्यात्मिक सभ्यता का केंद्र है, जहां उच्च कोटि के योगी, सिद्ध पुरुष और ज्ञानी संत निवास करते हैं। यहां का जीवन पूर्ण शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति से परिपूर्ण माना जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि शम्भाला तक पहुंच केवल भौतिक यात्रा से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए अत्यंत उच्च स्तर की आध्यात्मिक साधना और चेतना की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसे एक रहस्यमयी और दिव्य लोक की संज्ञा दी जाती है। कैलाश पर्वत के बारे में कई रहस्यमय बातें कही जाती हैं जैसे- कैलाश पर्वत पर आज तक कोई सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है। वहां अजीब ऊर्जा या आध्यात्मिक अनुभव की बातें कही जाती हैं। कई साधु-योगियों ने इसे दिव्य ऊर्जा केंद्र बताया है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इन दावों का प्रमाण स्पष्ट नहीं है। संभला लोक की अवधारणा एक आध्यात्मिक-पौराणिक रहस्य है, जिसे कुछ लोग कैलाश पर्वत के भीतर छिपा दिव्य लोक मानते हैं, जबकि अन्य आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताते हैं।

इस विषय में तीन प्रकार की धारणाएं हैं: (1) वास्तविक गुप्त स्थान-कुछ लोग मानते हैं कि यह हिमालय के भीतर छिपा वास्तविक क्षेत्र है। (2) सूक्ष्म या आध्यात्मिक लोक-कई आध्यात्मिक विद्वान कहते हैं कि शम्भाला भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म आयाम में स्थित है। (3) प्रतीकात्मक अवधारणा-कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह मानव चेतना के सर्वोच्च स्तर का प्रतीक है। सनातन मान्यता के अनुसार, यह भगवान शिव का निवास स्थान है। पर्वत के भीतर या आसपास एक गुप्त मार्ग या ऊर्जा क्षेत्र है जो संभला लोक तक जाता है। सामान्य व्यक्ति उस मार्ग को देख नहीं सकता, केवल उच्च आध्यात्मिक स्तर वाले योगी ही वहां प्रवेश कर सकते हैं। कुछ रहस्यवादी परंपराएं कहती हैं कि कैलाश के भीतर भूमिगत या सूक्ष्म लोक का प्रवेश द्वार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। यह पर्वत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई साधु-संतों और तिब्बती रहस्यवादी परंपराओं में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि कैलाश पर्वत के आसपास या उसके भीतर किसी सूक्ष्म मार्ग के माध्यम से शम्भाला तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि साधारण मनुष्य उस मार्ग को नहीं देख सकता। केवल वे साधक जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत हैं, इस रहस्य को अनुभव कर सकते हैं। इसी कारण कैलाश पर्वत को ''धरती का आध्यात्मिक ध्रुव'' भी कहा जाता है। हिंदू धर्मग्रंथों में शम्भल नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जहां भविष्य में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। यह उल्लेख विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार कलियुग के अंत में कल्कि अवतार शम्भल नामक स्थान में जन्म लेंगे और अधर्म तथा अन्याय का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। यह उल्लेख शम्भाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी शम्भाला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तिब्बती ग्रंथ कालचक्र तंत्र में शम्भाला का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें इसे एक अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक राज्य बताया गया है जहां धर्म और ज्ञान का सर्वोच्च विकास हुआ है। तिब्बती परंपरा के अनुसार शम्भाला के शासक को ''रिग्देन राजा'' कहा जाता है। भविष्यवाणी की जाती है कि जब संसार में अधर्म और अराजकता अत्यधिक बढ़ जाएगी, तब शम्भाला से धर्म की शक्ति प्रकट होकर विश्व में संतुलन स्थापित करेगी। संभला लोक के अस्तित्व को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ लोग इसे हिमालय के भीतर स्थित वास्तविक गुप्त स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान इसे भौतिक स्थान के बजाय सूक्ष्म आध्यात्मिक आयाम बताते हैं, जो केवल उच्च चेतना की अवस्था में अनुभव किया जा सकता है। वहीं कई आधुनिक शोधकर्ता इसे एक प्रतीकात्मक अवधारणा मानते हैं, जो मानव जीवन की आध्यात्मिक यात्रा और आदर्श समाज की कल्पना को दर्शाती है। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत की चोटी पर सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया। कई यात्रियों और साधकों ने यहां अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होने की बातें कही हैं। कुछ लोग इसे अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र मानते हैं।

हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इन रहस्यों की स्पष्ट पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, फिर भी आस्था और अध्यात्म की दृष्टि से कैलाश पर्वत का महत्व आज भी उतना ही गहरा है। कैलाश पर्वत और संभला लोक की अवधारणा मानव सभ्यता की उस जिज्ञासा को दर्शाती है जो भौतिक संसार से परे किसी दिव्य और उच्चतर सत्य की खोज में सदैव प्रयत्नशील रही है। चाहे इसे वास्तविक स्थान माना जाए, सूक्ष्म आध्यात्मिक लोक या एक प्रतीकात्मक कल्पना। यह विचार मानव मन में आशा, आस्था और आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा जगाता है। इस प्रकार कैलाश और शम्भाला का रहस्य केवल धार्मिक कथा भर नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना की उस अनंत यात्रा का प्रतीक है जो सत्य, ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज में निरंतर आगे बढ़ती रहती है।

मनोरंजन

98वें ऑस्कर समारोह के 'इन मेमोरियम' खंड में याद नहीं किए गए बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र

निज संवाददाता : बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र, जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया था, का सोमवार को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के इन मेमोरियम (श्रद्धांजलि) खंड में ज़िक्र नहीं हुआ। बड़ी बात यह कि इस साल का श्रद्धांजलि खंड हमेशा से 15 मिनट ज़्यादा चला, जिसमें हॉलीवुड के लेजेंड्स रॉब रेनर, डायने कीटन और रॉबर्ट रेडफोर्ड को सम्मान दिया गया। ज़्यादा समय के बावजूद, धर्मेंद्र का नाम ब्रॉडकास्ट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि, उन्हें एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (एएमपीएएस) के ऑफिशियल ऑनलाइन रोस्टर में पांच और भारतीय फिल्मी हस्तियों- एक्टर सरोजा देवी, मनोज कुमार, जयश्री कबीर, कोटा श्रीनिवास राव और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर एस. कृष्णास्वामी के साथ सूचीबद्ध

किया गया था। इससे पहले अवॉर्ड्स सीज़न के दौरान, धर्मेंद्र को फरवरी में रॉयल फेस्टिवल हॉल में 79वें बाफ्टा अवॉर्ड्स में ऑनरेरी मेंशन दिया गया था, जहां वह इन मेमोरियम सेगमेंट में शामिल होने वाले अकेले भारतीय एक्टर थे। 2018 में 90वें एकेडमी अवॉर्ड्स में, आइकॉन शशि कपूर और श्रीदेवी को सम्मानित किया गया, और एडी वेडर ने उन्हें म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दिया। 2021 में 93वें एकेडमी अवॉर्ड्स के स्पेशल सेगमेंट में इरफ़ान खान को ऑनरेरी मेंशन (मानद उल्लेख) दिया गया था। वहीं, इस बार धर्मेंद्र के अलावा, हॉलीवुड के दूसरे जाने-माने एक्टर ब्रिगिट बार्डोट, मैल्कम-जमाल वार्नर, जेम्स वैन डेर बीक और एरिक डेन को भी इस सेक्शन से बाहर रखा गया। मालूम हो कि धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद 24 नवंबर को उनके 90वें जन्मदिन से कुछ ही हफ़्ते पहले निधन हो गया। बॉलीवुड के ही-मैन ने 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से डेब्यू किया था। उन्होंने 1960 के दशक में 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'अनुपमा' और 'आया सावन झूम' के जैसी फ़िल्मों से शोहरत हासिल की, और फिर 'शोले',' धरम वीर', 'चुपके चुपके', 'मेरा गाँव मेरा देश' और 'ड्रीम गर्ल' में शानदार एक्टिंग करके बॉलीवुड के टॉप लीडिंग एक्टर्स में से एक बन गए। एक्टर ने अपने छह दशक से ज़्यादा के एक्टिंग करियर में 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। धर्मेंद्र की आखिरी बड़ी स्क्रीन फ़िल्म श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा 'इक्कीस' थी।

एक्टर विवियन डीसेना के घर आया नन्हा मेहमान

निज संवाददाता : प्यार की ये एक कहानी और मधुबाला जैसे मशहूर शोज के एक्टर विवियन डीसेना ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट में बताया कि अब उनका परिवार बड़ा हो गया है और उनके घर बेटा पैदा हुआ है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। विवियन की पुरानी को-स्टार रुबीना दिलाइक ने खुशी जताते हुए उन्हें और नौरान को मुबारकबाद दी। इसके अलावा बिग बॉस 18 के साथी रजत दलाल, अली गोनी, भारती सिंह और ईशा सिंह जैसे बड़े सितारों ने भी नए माता-पिता को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। विवियन ने साल 2022 में मिस्र की पत्रकार नौरान अली से शादी की थी। दोनों की मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। इस जोड़े की पहले से ही एक बेटी है जिसका नाम लियन है।

4000 करोड़ के बजट में बनी 'रामायण' पर्दे पर आते ही मचाएगी तबाही?

बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म

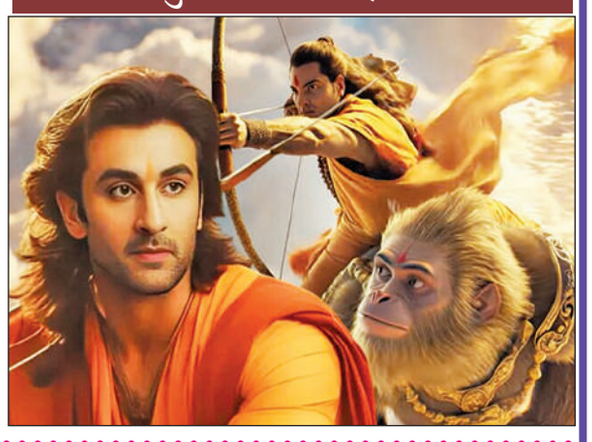

रणबीर कपूर की अपकमिंग रामायण के 4 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट की खूब चर्चा हो रही है। वहीं कहा जा रहा है कि ये फिल्म भारी भरकम बजट के बावजूद 'धुरंधर 2' को मात दे सकती है।

निज संवाददाता : रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है। फिल्म ने कमाई के इतने बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं कि हर कोई हैरान है। हालांकि एक 4000 करोड़ के बजट में बनाई जा रही फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि वो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी और धुरंधर 2 के सारे रिकॉर्ड भी मिट्टी में मिला देगी। दरअसल यहां रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित माइथोलॉजिकल ड्रामा 'रामायण' की बात हो रही है। इस फिल्म को लेकर अभी से फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं। बता दें कि अपकमिंग फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा यश, साई पल्लवी और सनी देओल भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिलहाल रामायण के बजट की खूब चर्चा हो रही है और इस भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है बताया जा रहा है। इसे दो हिस्सों में बनाया जा रहा है। इन दोनों फिल्मों की कुल लागत की कंफर्मेशन इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने की। इसका बजट इतना भारी भरकम है कि हर कोई इसके ब्रेक-ईवन (लागत वसूल होने) और रिकवरी के बारे में बात कर रहा है। बता दें कि इस दो-भाग वाली फ्रैंचाइज़ी का बजट 500 मिलियन यानी 4300 करोड़ रुपये है। डीएनईजी के नामित मल्होत्रा ने यूट्यूब पर प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में बात करते हुए इस लागत का खुलासा किया। रामायण की दोनों फ़िल्मों में से हर एक की लागत 2000 करोड़ मानी जा रही है। एसएस राजामौली के 550 करोड़ के भारी-भरकम बजट की तुलना में, इस बड़ी फ़िल्म का हर हिस्सा 263.63 फीसदी ज़्यादा महंगा है। इतनी ज़्यादा लागत को देखते हुए, फ़िल्म को बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त कमाई करनी होगी। इतनी ज़्यादा लागत के बावजूद, रामायण बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा सकती है। हालांकि 2000 करोड़ के बजट के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर सफल होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती है। पुष्पा 2 और बाहुबली के बाद अब धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। गौरतलब है कि पुष्पा 2 को 10 करोड़ से ज़्यादा और बाहुबली 2 को 6 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने देखा था। इन दोनों फ़िल्मों ने भारत में आसानी से 1000 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई की थी। वहीं धुरंधर 2 इन्हें भी मात देने की तैयारी कर रही है क्योंकि 8 दिन में ही धुरंधर 2 ने 650 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है और ये जल्द ही भारत में 1000 करोड़ी बनने वाली है। वहीं रणबीर कपूर की रामयण भी एक ऐसे सब्जेक्ट पर बनी है जो हर भारतीय को पसंद आएगी और जिससे लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हैं। ऐसे में रामायण कमाल कर सकती है; और अगर यह 15 करोड़ दर्शकों का आंकड़ा छू लेती है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इतने ज़्यादा दर्शकों के साथ, 2000 करोड़ की नेट कमाई का लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। ऐसे में ये धुरंधर 2 को धोकर रख सकती है। विदेशों में भी, रणबीर कपूर और यश की यह फ़िल्म धूम मचा सकती है। इसलिए, इस एपिक में दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर आसमान छूने वाले आंकड़े हासिल करने की क्षमता है, और भारी बजट के बावजूद, ये महा रिकॉर्ड बना सकती है।

लता और आशा के दौर में उभरी थीं अलका याज्ञनिक

अपने सुरों से करोड़ों दिलों का जीता मन

निज संवाददाता : बॉलीवुड संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, जो समय के साथ काफी पसंद की जाने लगती है। ऐसी ही एक आवाज है, अलका याग्निक की, जिन्होंने अपने सुरों से करोड़ों दिलों को छुआ है। 90 के दशक में जब संगीत का दौर अपने सुनहरे समय में था, तब कई दिग्गज गायिकाएं इंडस्ट्री पर राज कर रही थीं।

उसी दौर में अलका याज्ञनिक ने भी कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अलका याज्ञनिक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। उनकी मां, शुभा याज्ञनिक, एक शास्त्रीय गायिका थीं, जिनसे अलका ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने आकाशवाणी में गाना शुरू कर दिया था। यह उनके करियर की पहली सीढ़ी थी, जिसने आगे चलकर उन्हें बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बचपन में ही अलका अपनी मां के साथ मुंबई आ गईं।

यहां उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता राज कपूर से हुई। उनकी आवाज सुनकर राज कपूर काफी प्रभावित हुए, और उन्होंने उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल से मिलवाया। शुरुआत में उन्हें डबिंग आर्टिस्ट बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने सिंगिंग में ही करियर बनाने का फैसला किया। धीरे-धीरे उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिलने लगा। अलका याज्ञनिक को असली पहचान फिल्म तेजाब के गाने एक दो तीन से मिली। इस गाने ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। कयामत से कयामत तक, साजन, कुछ कुछ होता है, हम हैं राही प्यार के जैसे फिल्मों में उनके गाए गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी आवाज में इमोशन्स को जाहिर करने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे हर गाना खास बन जाता था। यह वह समय था, जब इंडस्ट्री में लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं का दबदबा था।

ऐसे माहौल में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अलका याज्ञनिक ने अपनी मेहनत और अलग अंदाज से खुद को साबित किया। उनकी आवाज नई पीढ़ी के लिए ताजगी लेकर आई, और उन्होंने अपनी पहचान एक अलग स्टाइल की सिंगर के रूप में बनाई। अलका याज्ञनिक ने अपने करियर में हजारों गाने गाए और कई भाषाओं में अपनी आवाज दी। उन्होंने कुमार सानू और उदित नारायण जैसे सिंगर्स के साथ मिलकर कई सुपरहिट गाने दिए। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उनके गाने आज भी रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खूब सुने जाते हैं। अवॉर्ड्स की बात करें तो अलका याज्ञनिक को कई बड़े सम्मान मिले हैं। उन्होंने 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड, 2 नेशनल अवॉर्ड और कई अन्य सम्मान अपने नाम किए हैं। भारत सरकार ने उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय :** 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइव रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय :** 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता,** मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)